

होता। बलिदान के बाद प्रेम, प्रेम नहीं रहता, परोपकार बन जाता है। आदर्श नहीं, घमंडी और बनावटी परोपकार।

Daily सच के हक में... E PHOTON REM



Pragya Jaiswal's Glammed Up...

'लापता लेडीज' के ऑस्कर नॉमिनेशन से खुश हैं हवलदार दुबे

INTERVIEW

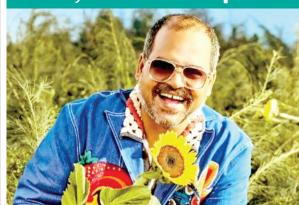
NEHA VERMA @ JSR: किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज इन दिनों ऑस्कर में नॉमिनेशन को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में दुबे जी का किरदार निभाने वाले एक्टर दुर्गेश कुमार अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इम्तियाज अली की फिल्म 'हाईवे' से अपने फिल्मी कॅरियर की शुरुआत करने वाले दुर्गेश ने 'द फोटोन न्यूज' संग अपनी खुशी शेयर की।

Q. क्या अब आप अपनी प्राइस बढ़ाएंगे?

> मेरा यह कहना है कि मैं जेनुइनली मिनिमम जो प्राइस होता है। या बोल सकते हैं, जो मेहनताना, मुझे मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस को मिलना चहिए, वो तो जरूर डिमांड करूंगा।

इम्तियाज अली की फिल्म 'हाईवे' से अपने फिल्मी कॅरियर की शरुआत करने वाले दुर्गेश से 'द फोटोन न्यूज' की विशेष बातचीत

कहा, अब फीस भी बढ़ेगी...



Q. लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है. पहला रिएक्शन क्या था?

मैं भुवनेश्वर में एक इवेंट अटेंड कर वापस मुंबई आ रहा था। फ्लाइट से उतरते ही मैं अनुराग कश्यप जी की एक मूवी का एक्शन रिहर्सल करने डायरेक्ट सेट चला गया। वहीं सेट पर मुझे पता चला कि ये फिल्म ऑफिशियल गई है। सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई कि उसमे मेरा भी एक इंपोर्टेंट पार्ट है। संयोग की बात है कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे मौका मिले, तो मैं ऑस्कर में भी फिल्म ले जोऊंगा और ये बात ऐसे सच होगी, यह नहीं सोचा था।

Q. क्या सपोर्टिव किरदारों को भी इस तरह के अचीवमेंट का फायदा मिलता है?

> जी बिल्कुल, पूरे मार्केट में खबर है कि दुर्गेश भी इस मूवी में थे, जो ऑस्कर के लिए गई है। वहीं मैंने कई इंटरव्यू किए, जिसमें पत्रकारों ने भी मुझे बोला कि हमें इस फिल्म में आपका दुबे जी का कैरेक्टर बहुत पसंद है। लोग अब साइड के किरदारों को भी तवज्जों देते हैं। उनकी भी अब तो प्रमोशन होती है। ऐसे ही मौके मिलते हैं।

चतरा व कोडरमा को दी ८४१ करोड़ रूपये से अधिक की सौगात

गरजे सीएम हेमंत सोरेन- मोदी

सरकार को बताया अव्वल भ्रष्ट

0. क्या एक्टर को कमर्शियली भी फायदा होता है?

दफोटोनन्यूज Published from Ranchi

जी हां, कमर्शियली भी काफी फायदा होता है। मतलब एक एक्टर के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बढता है। आप अपनी फीस पर भी बात करते हैं। नहीं भी करें, तो सामने वाला इस तरह की अचीवमेंट्स को देखकर प्रति दिन के हिसाब से पेमेंट भी बढ़ा देता है। लोग थोड़ा आपको लेकर सोचने लगते हैं। जैसे मुझे अब बहुत सारा काम मिल रहा है। मेकर्स भी फिल्म में की-रोल के लिए आपको हायर करने लगते है।

Q. कितने साल का स्ट्रगल रहा आपका?

टोटल अगर में आपको बताऊं तो, मैं वैसे स्ट्रगल नहीं बोलता लेकिन स्ट्रगल तो है ही। हालांकि मैं इसने अभी भी लर्निंग के रूप में ही लेता हूं। मैं अपने आपको एक्टिंग स्टूडेंट ही मानता हूं। मुझे इस फील्ड में आए तकरीबन 25 साल तो हो ही गए होंगे। मैंने पहला प्ले 6 फरवरी 2002 में किया था और अभी 31 मई 2024 में मेरी फिल्म डेढ़ बीघा जमीन, जियो सिनेमा पर आई है। बस यही सिलसिला चल रहा है।

Q. आपकी आपके टीम से बातचीत या कोई बधार्ड संदेश?

> जी नहीं। मेरी सिर्फ रवि किशन जी से थोड़ी बहुत बातचित वॉट्सऐप पर होती है। तो वहीं पर उन्होंने बंधाई दी।

Q. क्या आपको लगता है कि फीस के तौर पर आपको जितना मिलना चाहिए, उतना अब तक नहीं मिल पाया ?

≻जी हां, ये तो थोड़ा सा है.. निर्देशक, कास्टिंग डायरेक्टर ये सब मुझ सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स मुझपर भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं और यही वजह भी है कि फीस मेरी लिमिटेड होती है। ये बात मुझे बहुत खराब लगती है। खैर, अपना भी वक्त आएगा



सेंसेक्स : 84,914.04 निफ्टी : 25,940.40

चांदी 98.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

27 सितंबर को होगी हेमंत कैबिनेट की मीटिंग

RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को शाम चार बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इसमें कई प्रस्तावों पर महर लग सकती है। ऐसा समझा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व संभवत दो-तीन ही कैबिनेट की मीटिंग होगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई अहम फैसले ले सकती है।अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार राज्यभर के आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए मानदेय बढाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है।

जम्मू-कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग आज

JAMMU : जम्मू-कश्मीर विधानसभा

चनाव के दसरे चरण में बधवार को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह विधानसभा क्षेत्र घाटी और जम्म् संभाग के तीन-तीन जिलों में फैले हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें 1,056 शहरी मतदान केंद्र और 2,446 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। बता दें कि 18 सितंबर को मतदान के पहले चरण में अनुमानित 61.38 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

बिहार में नदी में नहाने के दौरान इबकर छह की मौत

PATNA: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली तीन बहनें जीतिया पर्व के मौके पर सोती नदी में नहाने गई थीं। नहाने के दौरान ही तीनों बहनों गहरे पानी में चली गईं और डूबकर उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपनी, मंज्र, चाहत कुमार और मुकुंद कुमार के रूप में हुई है। दोनों दसवीं के छात्र थे।

PHOTON NEWS CHATRA:

मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा में थे। उन्होंने ईटखोरी स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार', कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात दी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग धन-बल से संपन्न हैं। झुठ-सच करने में माहिर हैं। ऐसे में गरीब लोगों को लगता है कि ये जो बोलते हैं, वो सही बोलते होंगे। गरजते हुए उन्होंने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार देश की अव्वल भ्रष्ट सरकार है। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की 702 विकास योजनाओं का तोहफा चतरा और कोडरमा जिले लाभुकों के बीच 736 करोड़ को दिया। लगभग 5 लाख रुपये से ज्यादा की परिसंपत्तियों सिखयों में नियुक्ति पत्र का भी

आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम में बड़ी जनसभा को किया संबोधित



>कहा- पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता झारखंड

>गरीबों का काम करने से हो रही तकलीफ >2021 से चल रहा है 'सरकार आपके द्वार'

≽ मां भद्रकाली मंदिर में की पूजा-अर्चना

छत्तीसगढ़ में अडानी को मिली खदान 20 साल बीजेपी ने लुटा

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ में अडानी को खदान मिल गई। वहां के गांव के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, वहां के आदिवासियों को बेदखल करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। यह कार्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये लोग जंगल उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं, अगर जंगल उजड गया तो पर्यावरण, दलित, आदिवासी सब खत्म हो जाएगा। अब यहां भी व्यापारियों को एक-एक कर बैढाने की तैयारी है। लेकिन, आने वाले समय में ऐसा नीति निर्धारण करेंगे कि इस राज्य की सारी खनिज संपदा का हिसाब किताब स्थानीय लोग करेंगे, उसके बाद ही खनिज राज्य से बाहर जाएगा।

मडरा रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर एक दर्जन मुख्यमंत्री

हेमंत ने कहा कि भाजपा के लोग मंईयां योजना की काट के तौर पर योजना लेकर आने वाले हैं. लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों 20 वर्षों तक उन्होंने बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी। बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। विपक्ष में खलबली मची हुई है। हम सरकार की कार्य योजना को लेकर जिला-जिला घम रहे हैं और

ये लोग कैसे चुनाव में वोट खरीद सकें, इसके लिए गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर एक दर्जन मुख्यमंत्री पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। हेमंत ने कहा कि विपक्ष जातिवाद, परिवार अगडा-पिछडा,सिख-इसाई करके चनाव लड़ता हैं। लोकसभा चनाव में आपने देखा किस तरह से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन्होंने फैलाया।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 20

साल तक भाजपा सत्ता में रही। आपकी

सरकार के 4 साल में, 2 साल कोरोना

महामारी में जीवन और जीविका बचाने

में गुजर गए, 2 वर्ष तक झूटे आरोप

लगांकर भाजपा परेशान करते रही।

हर दिन कुछ ना कुछ अडंगा ये सभी

काम में लगाते रहें। मैं लोकसभा के

चुनाव में शामिल न हो सकूं, इसके

लिए इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया।

अगर मैं जेल से बाहर होता तो, इनसे

सभी सीट हम छीन कर रहते।

आपकी सरकार अच्छा कार्य कर

भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी, इससे यूथ में नहीं बढ़ेगी अनैतिकता सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कांसेप्ट नहीं : सुप्रीम कोर्ट

AGENCY NEW DELHI: एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

है कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कांसेप्ट मानना गलत है। इससे यूथ में अनैतिकता नहीं बढ़ती है। इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा लोगों का मानना है कि सेक्स एजकेशन भारतीय मल्यों के खिलाफ है। इसी वजह से कई राज्यों में यौन शिक्षा को बैन कर दिया गया है। इसी विरोध की वजह से यवाओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती। फिर वे इंटरनेट का सहारा लेते हैं, जहां

अक्सर भ्रामक जानकारी मिलती बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचुड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले

एक व्यापक रिसर्च का दिया हवाला

का वितरण किया। मौके पर पोषण वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने

कोर्ट ने कहा है कि एक रिसर्च से पता चला है कि सही सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। महाराष्ट्र में 900 से ज्यादा किशोरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों को प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की सही जानकारी नहीं थी। उनमें जल्दी यौन संबंध बनाने की संभावना ज्यादा थी। यह बहुत जरूरी है कि हम सेक्स

को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध है।

बारे में सभी को सही जानकारी दें, ताकि हम सेक्स हेल्थ के नतीजों को बेहतर बना सकें। बच्चों के खिलाफ अपराध सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं रहते हैं। उनके वीडियो, फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग के जरिए ये शोषण आगे भी चलता है। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा

एजकेशन के बारे में गलत धारणाओं को

दूर करना शुरू करें। इसके फायदों के

था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है, तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की न हो।

अब तमिलनाडु में

अब तमिलनाडु में एक और हेल्थ केयर कर्मी के साथ रेप का मामला स्थित थेनी की एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात लोगों ने पीड़ित किडनैप किया था। इसके बाद गैंगरेप किया। फिर उसे डिंडीगुल गए। रेलवे स्टेशन पर घायल पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी। पीड़ित को डिंडीगुल सरकारी प्रदीप ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मर्डर हुआ था। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। पुलिस ने 10 आरोप में गिरफ्तार किया था। वह अभी सीबीआई हिरासत में है। घटना के विरोध में बंगाल सहित देशभर के जुनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 22 अगस्त को बंगाल छोड़कर सभी राज्यों में डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली



नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप

DINDIGUL: कोलकाता के बाद

सामने आया है। राज्य के डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डिंडीगुल जिला एसपी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप-अगस्त को संजय रॉय नाम के एक सिविक वालंटियर को रेप-मर्डर के थी। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स 42 दिन हड़ताल के बाद 21 सितंबर को ड्यूटी पर लौटे थे।

सीईसी ने कहा- समय पर कराएंगे झारखंड विधानसभा का चुनाव

• दौरे के दूसरे दिन

PHOTON NEWS RANCHI: मंगलवार को भारत निर्वाचन

आयोग की टीम के झारखंड दौरे का दूसरा दिन था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के नेतृत्व में दूसरे दिन भी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में राज्य के सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जोनल आईजी, सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, सभी डीआईजी और सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक हुई। आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए। सीईसी ने स्पष्ट किया कि समय पर झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा। कहा कि बुधवार को जम्मू कश्मीर का दसरे चरण का चनाव है। उसके बाद महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी। उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट एजेंसी को भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर को सील करने के आईजी-डीआईजी व डीसी-एसपी के साथ की मीटिंग

🌘 समय पर पहल करते हुए आवश्यक समन्वयात्मक कदम उटाने का दिया निर्देश

आदेश दिए गए हैं, जिससे किसी की आवाजाही नहीं हो। राज्य के पदाधिकारियों से मिले इनपुट, सझावों, प्रतिवेदनों आदि से अवगत कराते हुए आयोग ने संबंधित विषयों पर ससमय पहल करते आवश्यक हुए समन्वयात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। मख्य निर्वाचन आयुक्त ने डीईओ और एसपी को शराब, नकदी और शुल्क के किसी भी अवैध प्रवाह के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होगा चुनाव

चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। रांची में हुई इस समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडियाकर्मियों से बात की। कहाँ कि हर हाल में चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से होगा, इसमें किसी तरह की संलिप्तता अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों की पाई जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के चार जिलों खासकर चतरा, रांची, खूंटी, लातेहार में इंग्स एवं अन्य मादक पद्धार्थ की आवाजाही रोकने का सख्त निर्देश देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधि के जरिए प्रलोभन देने पर रोक लगाया जाएगा। मुख्य चुनाव

आयुक्त ने कहा कि चुनाव को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रोल टू पोल के तहत मतदाता सूची साफ सुथरी हो इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय मिले और मतदान केंद्र पर वोटर को सारी सविधाएं मिले। इसके लिए अधिकारियों को विस्तार से बताया गया है। चुनाव आयोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गंभीर है। राजनीतिक दलों की मांग पर आयोग के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी मुहैया कराए जाएंगे साथ ही कुछ जगहों से शिकायत मिली थी कि 2 किलोमीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं है, वहां भी मतदान केन्द्र मुहैया कराया जाएगा।

जमीन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर चलेगा मुकदमां, रिट खारिज

AGENCY BENGALURU: मंगलवार को कर्नाटक के चीफ

मिनिस्टर सिद्धारमैया की उस याचिका को हाई कोर्ट की नागप्रसन्ना पीठ ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी थी। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 12 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धारमैया का प्रतिनिधित्व किया था।



फैसले के बाद इस्तीफा देने से किया इनकार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गढबंधन (राजग) सरकार उनके नेतत्व वाली सरकार के खिलाफ बदले की राजनीति में संलिप्त है। सिद्धरमैया ने याचिका खारिज होने के बाद विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर की जा रही मांग को भी दुकरा दिया।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में 600 मिलियन डॉलर का किया सौदा

भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना आर्मेनिया

भारत अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए

दूसरे बड़े देशों से हथियारों का आयात ही नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों में हथियारों का निर्यात भी करता है। पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित पहाड़ी देश आर्मेनिया भले ही किसी अन्य देश से संघर्षरत न हो, लेकिन भारत से हथियार खरीदने वाला वह सबसे बड़ा देश बना गया है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम,आकाश एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम, हॉवित्जर, एंटी-टैंक रॉकेट और एंटी-ड्रोन उपकरण और गोला-बारूद का आयात किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष २०२४-२५ की शुरूआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल 600 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के बीच सैन्य सहयोग निरंतर बढ रहा है। पिछले चार वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे

बडा आयातक बनकर उभरा है।

नई दिल्ली व आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के बीच बढ़ रहा सैन्य सहयोग मजबूत हो रहे कूटनीतिक रिश्ते



सक्षम हो रही आर्मेनिया की सेना

भारतीय वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिनाका मल्टीपल-लॉन्च रॉकेट सिस्टम और आकाश एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद पर सौंदे करने के बाद पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बडा आयातक बन गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मौजब वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरूआत तक भारत से आमेंनिया द्वारा खरीदे गए हथियारों की क़ुल मात्रा 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों का आधिकारिक और कूटनीतिक तरीके से सैन्य सहयोग करने की अनुमति असर तब दिखा, जब 2023 में येरेवन मिलेगी। आर्मेनिया पहले हथियारों और ने भारत के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में अपने दूतावास में एक रक्षा अताशे को

नियुक्त किया। यह निर्णय २०२२ में आर्मेनिया से भारतीय हथियार निमाताओं के साथ कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। कुल 245 मिलियन डॉलर के इन सौदों में भारतीय मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एंटी-टैंक रॉकेट और गोला-बारुद का अधिग्रहण शामिल था। भारत में अर्मेनियाई रक्षा अताशे की मौजूदगी से येरेवन और नई दिल्ली को

गोला–बारूद की आपूर्ति के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर था। आर्मेनिया ने रूस के जरिये 2011 से 2020 तक प्रमुख हथियारों का आयात ९४ प्रतिशत तक किया था। इस अवधि के दौरान मास्को ने येरेवन को बख्तरबंद कार्मिक वाहक, वायु रक्षा प्रणाली, कई रॉकेट लांचर और टैंक की आपूर्ति की। इसके अतिरिक्त 2016 में रूस ने 300 किलोमीटर (186 मील) की अनुमानित सीमा के साथ इस्कैंडर शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति की।

विकसित भारत का सपना साकार करने में युवाओं की भूमिका अहम : कुलाधिपति

पीएचडी समेत विभिन्न संकायों के अव्वल 116 छात्र-छात्राओं को दी गई उपाधि व गोल्ड मेडल

राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षा समारोह में बतौर मख्य अतिथि छात्रों को उपाधि व गोल्ड मेडल प्रदान करने के उपरांत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने में युवाओं की भूमिका अहम है। कहा कि युवा सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ज्ञान उपयोग करें। राज्यपाल ने कहा कि



छात्रा को प्रमाण पत्र प्रदान करते राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगावार

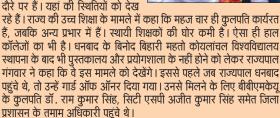
विकास को नई दिशा और गति सके। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान करते हुए कहा कि यह उनके जीवन में नए अध्याय की शुरूआत है। उनके समक्ष कई चुनौतियां हैं और अपार संभावनाएं व अवसर

है। युवा कंधों पर ही जनजातीय उत्थान और गौरव को अक्षुण्ण इसके लिए सामहिक प्रयास करना होगा। अध्ययन व शोध से ऐसी चुनौतियों का समाधान निकालें,

में प्रदेश की अलग व व्यापक पहचान बन सके। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ तीर कमान से आजादी हासिल करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और हुल के नायक सिदो-कान्हू मुर्मू के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, जो कि हर्ष और गौरव का विषय है। इससे पूर्व केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रो. डॉ. क्षिति भूषण दास ने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब भारत की पहचान सांस्कृतिक संपन्नता से हो। कहा कि आत्मनिर्भरता सबसे अहम है, इसलिए हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर

उच्च शिक्षा पर यहां नहीं दिया गया ध्यान : राज्यपाल DHANBAD : झारखंड की उच्च शिक्षा में सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। यहां

इस दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक समेत अन्य संसाधनों की कमी है। ये बातें राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंगलवार को धनबाद परिसदन में कहीं। वे दुमका से रांची सडक मार्ग से जाने के क्रम में धनबाद पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि वे राज्य के



विकसित भारत की शुरूआत हो चकी है। वर्तमान में भारत परे

प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था वाला

हाथापाई का बदला लेने को ऑटो में रखी थी पिस्टल SARAIKELA: सरायकेला-• पुलिस ने मानगो जवाहरनगर

खरसावां जिले के कपाली थाना के रहने वाले रिजवान रजा की पुलिस ने बीते दिनों एक को किया गिरफ्तार ऑटो से मिले पिस्टल के मामले को सुलझा लिया है। इस संबंध में पुलिस ने रिजवान रजा उर्फ शेख अयान उर्फ सरकार को गिरफ्तार किया है, जो मानगो जवाहरनगर रोड नंबर 12 का रहने वाला है। दरअसल 17 सितंबर को कपाली ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटो में कुछ लोग पिस्टल लेकर घम रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस ने छानबीन पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शुरू की और उस ऑटो को पकड़ा। ऑटो में चार लोग सवार थे। तलाशी के क्रम में ऑटो से एक पिस्टल बरामद किया गया। हालांकि जब हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की गई, तो

थी। वे लोग उस युवक को नहीं जानते थे। बाद में उन लोगों ने ऑटो खड़ी कर शराब पी थी। इस बीच क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। हालांकि बाद में पुलिस ने जांच की और ऑटो में पिस्टल रखने वाले रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान पूर्व में पांच बार सिदगोड़ा, मानगो, बिष्टुपुर और रेल थाना से जेल

मुरहू में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

PHOTON NEWS PALAMU: जिले के मुरह थाना क्षेत्र में छह दिन पूर्व गत बुधवार को छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रही एक नाबालिग आदिवासी छात्रा को रास्ते से अगवा कर सामृहिक दुष्कर्म के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुरहू थानांतर्गत बोराटोला चतराडीह गांव के मारियानुस बोदरा उर्फ हड़ाम (23), मानटोला चतराडीह गांव के सोनल बोदरा उर्फ गोविंद (20) तथा सांगेटोली चतराडीह के मारकुस बोदरा उर्फ जामड़ा (19)

शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपितों ने

पुलिस के समक्ष अपना अपराध

स्वीकार करते हुए इस कांड में

शामिल अपने अन्य पांच

तेज रफ्तार वाहन की

चपेट में आकर एक

की मौत, तीन घायल

LOHARDAGA: नेशनल हाईवे

75 कुडू – रांची मुख्य पथ पर बिहारी

ढाबा के समीप अज्ञात कार की चपेट

में आने से एक व्यक्ति की मंगलवार को

मौत हो गई । जबिक भागने के क्रम में

लोग घायल हो गए हैं। तीनों का इलाज

करने वाला मजदूर अशोक केसरी कुडू

कार की ठोकर से बाइक सवार तीन

कुडू सीएचसी में चल रहा है। बताया

जाता है कि कुडू के होटल में काम

से काम करने के बाद साइकिल से

अपने घर लौटने के बाद घर के बाहर

निकलकर टहल रहा था। इसी बीच

कुडू की तरफ से तेज रफ्तार से जा

रही कार ने बिहारी ढाबा के समीप

अशोक केसरी को अपनी चपेट में ले

लिया । इससे अशोक केसरी गम्भीर

रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के

कुडू सीएचसी पहुंचाया गया, जहां

सहयोग से घायल को इलाज के लिए

इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई।

वहीं दूसरी ओर घटना के बाद भागने

के क्रम में कार ने बाइक सवार को

अपनी चपेट में ले लिया। इससे तीन

लोग पुनिता तिर्की कैरो, गितिलगढ

रहा युवक घायल हो गए तीनो का

इलाज कुडू सीएचसी में चल रहा है।

निवासी बोलरी महली और बाइक चला



PALAMU: नेशनल हाईवे 39

डालटनगंज-रांची मुख्य पथ पर

सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल में

पिकअप सवारी गाड़ी ने रौंद दिया।

एमआरएमसीएच में ले जाया गया,

जहां कुछ देर इलाज चलने के बाद

उसकी मौत हो गई। छात्रा की

पहचान पोलपोल के चक बरेवा

निवासी संजय पांडे की 23 वर्षीय

पुत्री साक्षी पांडे के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि साक्षी पांडे

मेदिनीनगर कॉलेज जाने के लिए

पोलपोल से टेंपो में सवार हुई थी।

कुछ देर बाद घर से फोन आया कि

रास्ते में कहीं झिंगी का पत्ता मिले तो

लेते आना। छात्रा टेम्पो से उतर कर

झिंगी का पत्ता तोडने के लिए सडक

पार कर रही थी। इस बीच

डालटनगंज की ओर से तेज रफ्तार

से आ रही पिकअप सवारी गाड़ी ने

हालत

सडक पार कर रही



6063), मोबाइल फोन और घटना के समय एक आरोपित द्वारा पहनी हुई शर्ट और जींस पैंट को बरामद कर लिया है। यह जानकारी खुंटी

पलामू में सड़क पार कर रही

छात्रा को पिकअप ने रौंदा, मौत

छात्रा को

एसडीपीओ वरूण रजक ने आरोपितों की में खराब हो गई थी। आरोपित अपनी मोटरसाइकिल को ठीक कराने के प्रयास में थे। उसी दौरान स्कूल से अकेली पैदल घर लौट रही 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को

घटनास्थल पर मौजूद वाहन

उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर

हालत में छात्रा को एमआरएमसीएच

ले जाया गया, यहां कुछ देर इलाज

चलने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद चालक पिकअप

लेकर भाग निकला और कुछ दूर

आगे जाने के बाद पोलपोल और

लहलहे के बीच वाहन लगाकर

फरार हो गया। सूचना मिलने के

बाद सतबरवा थाना पुलिस ने

कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद

से पिकअप सवारी गाडी को जब्त

कर थाना ले आई है। मामले में

अपने अन्य दोस्तों को बुलाकर छह आरोपितों ने छात्रा के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य आरोपित वहीं पर खड़े रहकर पहरेदारी करते रहे। बताया गया कि पीड़िता के साथ आरोपितों का पूर्व से कोई जान पहचान नहीं थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुंटी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआइटी का गठन किया। गठित एसआईटी टीम द्वारा गहन तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त उक्त आरोपितों को पकड़कर जब उनसे पूछताछ की, तो मामले का खुलासा हो गया।

रिश्वत लेते लिपिक को एसीबी ने किया गिरफ्तार

HAZARIBAG : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हजारीबाग जिले प्रादेशिक



कच्छप को मंगलवार को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ब्यूरो को लिखित राज कुमार ने आवेदन दिया था कि विजय बस (जेएच02एभी 8861) जो देवघर रांची मार्ग पर चलता है। इसका परिमिट का रिनुअल करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय हजारीबाग में कार्यरत लिपिक विकास कच्छप के जरिये परमिट रिनुअल करने के एवज में छह हजार रिश्वत की राशि की मांग कर रहे है। शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे। जांच के दौरान आरोप सत्य पाया गया। एसीबी टीम ने विकास कच्छप को छह हजार

गिरिडीह में १०४९ पदों पर बहाली के लिए आज लगेगा रोजगार मेला GIRIDIH : श्रम, नियोजन,

विभाग, झारखंड सरकार की ओर से बुधवार को झंडा मैदान गिरिडीह में रोजगार मेला लगाया जाएगा। जिला नियोजनालय आयोजित किए जा रहे इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए 23 कंपनियों ने सहमति जताई है। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक इस रोजगार मेले में 1049 पदों पर बहाली के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में मैकेनिकल फिटर, कटर, हेल्पर, इलेक्ट्रिशयन, डाटा ऑपरेटर, शिक्षक, कुक, गार्ड, मेकैनिक, फोरमैन, ड्राइवर, ट्रेनी समेत अन्य पदों पर भर्ती होगी। चयनित अभ्यर्थियों को बतौर मानदेय न्यूनतम आठ सोरेन ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। वे मंगलवार को तोरपा

हेमंत सरकार ने महिलाओं और युवाओं के साथ किया छल : सेट



संजय सेट के साथ मंच पर मौजूद माजपा के नेता

KHUNTI : रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने पांच साल तक युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ छल किया। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के समय 25 हजार प्रति पांच एकड़ जमीन पर दिये जाते थे लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर किसानों का गला घोंट दिया। मुख्यमंत्री हेमंत

के ब्लॉक मैंदान में आयोजित परिवर्तन यात्रा में आये लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने राज्य को डुबोने का काम किया। पीएम सड़क योजना से गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में पांच वर्षों तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता की गाढ़ी कमाई

उन्होंने पिस्टल के बारे में कोई भी

जानकारी से इंकार किया। ऑटो

चालक ने बताया कि 17 सितंबर

को वे लोग पटमदा की ओर गए

थे, जहां रास्ते में एक युवक के

साथ विवाद के बाद हाथापाई हुई

एड्स जागरूकता अभियान को लेकर की गई बैठक LOHARDAGA: उप विकास

आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एचआईवी एडस जागरुकता अभियान को लेकर बैठक जिला परिषद कार्यालय स्थित सभाकक्ष में हुई। बैठक में सदर अस्पताल के एचआईवी, आईसीटीसी परामर्शदात्री डॉ अर्चना प्रसाद और सिनी के क्षेत्रीय समन्वयक ओमप्रकाश शर्मा द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में चलने वाले एचआईवी-एड्स जागरुकता अभियान के बारे जानकारी दी गयी। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस अभियान को सफल तरीके से आयोजित करने और जागरुकता कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि लोगों में एड्स के प्रति के तरह की भ्रांतियां हैं और जानकारी का अभाव है। जब किसी को एड्स होता है तो वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है जो कि

केंद्र के दबाव में ममता ने खोला एनएच : शुभेंद्र

बंगाल के नेता प्रतिपक्ष का दावा 90 प्रतिशत बंगाली परिवार देगा भाजपा को वोट

BOKARO : झारखंड में परिवर्तन सभा को संबोधित करने मंगलवार को बोकारो पहुंचे पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शभेंद अधिकारी ने ममता बनर्जी व हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला। कहा कि दोनों प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक ओर इंडी गठबंधन एकजुटता का परिचय देता है, दुसरी ओर ममता बनर्जी एनएच को 72 घंटों के लिए बंद कर झारखंड के वाहनों को रोक देती हैं। इस पर जब हमने गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से बात की, तब ममता बनर्जी को सड़क खोलना पड़ा। एनएच का मालिक भारत सरकार है, न कि ममता बनर्जी। कहा कि जिस प्रकार ममता बनर्जी को रोहिंग्या व बांग्लादेशी मसलमानों से प्रेम है. अब यही प्रेम झारखंड के रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हो गया



पत्रकारों को संबोधित करते शुमेंदु अधिकारी

एक माह तक झारखंड में रहूंगा

शभेंद्र अधिकारी ने कहा कि हेमंत सरकार को विदा करने के लिए एक माह झारखंड में रहूंगा। यदि हेमंत सरकार लौटी तो राज्य में बांग्लादेशी इस कदर भर जाएंगे कि हमें न तो पूजा पाठ करने देंगे और न ही हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। जनजातीय समाज को अपना त्योहार मनाना मुश्किल होगा। हमारे साथ झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कमार बाउरी जी हैं। 2024 में झारखंड से इंडी गठबंधन को विदा करेंगे, 2025 में ममता बनर्जी को हटाने का काम करेंगे। झारखंड में रहने वाले 90 प्रतिशत बंगाली समाज के लोग भाजपा को ही वोट देंगे। चूंकि वे पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं।

है। वे यहां के जनजातीय समाज का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। यह चुनाव किसी दुसरे मुद्दे का नहीं,

बल्कि विधानसभा चुनाव तय करेगा कि यह जनजातीय प्रदेश रहेगा या पश्चिम बंगाल के तरह स्थिति भयावह हो गई है। हमारे बांग्लादेशी मुसलमान लूट रहे हैं। कई पंचायत, जो आदिवासी बहुल थे अब बांग्लादेशी मुसलमान बहल हो गए हैं। अपने को बाहरी कह जाने पर कहा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार व ओडिशा चारों भाई रहे हैं। इसलिए इन प्रदेशों की भाषा, रहन-सहन व संस्कृति एक है। सीमा व नाम बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। झारखंड में परिवर्तन की लहर : जमशेदपर में प्रधानमंत्री एवं गहमंत्री की सभा में जो जनसैलाब उमडा. इससे परिवर्तन स्पष्ट है। जनजातीय समाज, सनातन समाज के लिए यह अंतिम चुनाव है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल रोहिंग्या व बांग्लादेशी मुसलमान 35 प्रतिशत हो गए हैं।

महिला प्रताड़ना पर सुनवाई के दौरान आयोग के कड़े तेवर से पुलिस पदाधिकारियों की पेशानी पर बल

इन्ववायरी के नाम पर दोस्ती निभाएंगे तो आना पड़ेगा दिल्ली : आयोग

PHOTON NEWS DUMKA: राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता देवी की तल्खी के सामने पुलिस महकमा के अधिकारियों के पेशानी पर बल पड़ रहे थे। मंगलवार को दुमका के इंडोर स्टेडियम में संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, गोड्डा ओर साहिबगंज जिले में दर्ज महिलाओं की प्रताड़ना से संबंधित मामलों में सुनवाई हुई। इस दौरान गोड्डा जिले में दर्ज अपराजिता गौतम नामक महिला के मामले की सुनवाई करते हुए ममता कुमारी उस वक्त भड़क गईं, जब उन्हें वहां से आए पुलिस के पदाधिकारी सही जानकारी देने की बजाए आनाकानी करने लगे। ममता देवी ने उनकी कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि गोड्डा थाना की पुलिस उस महिला के साथ अन्याय कर रही है। इस पर जब पुलिस पदाधिकारी ने

अपनी बातों का रखना चाहा तो



उन्होंने पूछा कि कौन है थानेदार। जब सही समय पर आयोग की नोटिस के बारे में जानकारी तक नहीं दिया, उसे कैसे थाना प्रभारी बना दिया गया है। कहा कि इन्क्वायरी के नाम पर अगर दोस्ती निभाएंगे तो दिल्ली आना पड़ेगा। इस दौरान आयोग के कड़े तेवर को देखकर मौके पर मौजूद सभी चार जिलों से आए पुलिस के पदाधिकारियों के हाथ-पांव फूल रहे थे। एक अन्य मामले में गोड्डा से फरियाद लेकर कविता देवी आई थीं। उन्होंने पीसीआर के जरिए अपने श्वसुर समेत अन्य सदस्यों पर प्रताड़ित व मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज कराया गया है। पीड़िता का कहना था कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में वहां से पुलिस पदाधिकरी को डपटते हुए ममता देवी ने कहा कि इतनी भी जानकारी नहीं है कि आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए अलग से

फाइल तैयार की जाती है। 2018 वाले पुलिस बैच को अभी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। इसी क्रम में मौके पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को कहा कि जो भी अपने साथ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट लेकर नहीं आए हैं, वे लोग बिना रिपोर्ट जमा कराए नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही कई पुलिस कर्मी एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। दुमका नगर थाना में दर्ज प्रियांशु गुप्ता के मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीएसपी से कहा कि क्या पीड़िता ने जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, उसके पास पैरवी ज्यादा है। आखिर ऐसी कौन-सी बात है कि पीड़िता को न्याय के लिए आयोग के समक्ष गुहार लगानी पड़ रही है। दुमका नगर थाना की ही रचना देवी के मामले में भी ममता कुमारी ने पुलिस की कार्यशैली पर काफी नाराजगी जताई। रचना का आरोप

है कि पुलिस उसकी नहीं सुनती है और इसकी वजह से विरोधी पक्ष उसे धमकाते हैं। इस पर ममता देवी ने कहा कि अगर पुलिस डराती या नहीं सुनती है तो उन्हें फोन करें। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान गोड्डा के जयकिशोर सिंह, साहिबगंज राजमहल की कल्याणी देवी, बड़हरवा की जुलेखा देवी समेत कई महिलाएं फरियाद लेकर आयोग के समक्ष पहुंचीं थी। कल्याणी देवी के मामले में सुनवाई के दौरान वहां की महिला पुलिस पदाधिकारी के स्तर से की गई कार्रवाई की आयोग सदस्य ने सराहना की। वहीं दुमका की दुधानी पंचायत की मुखिया जुली मरांडी भी आयोग के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। उनका कहना था कि वर्ष 2022 में उनके साथ हुई मारपीट की घटना में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इस पर नगर

थाना के थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तार हो गई है। दो फरार हैं जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि आदिवासी मुखिया ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। जनसुनवाई में कुल 30 मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान पूर्व में महिला उत्पीडन से संबंधित पत्रावलियों के बारे में हुई कार्रवाईयों की अद्यतन जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में महिला उत्पीडन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक मामले में संबंधित केस के इंचार्ज आफिसर तथा आवेदनकर्ता से जानकारी ली गई। सभी मामलों आयोग द्वारा पदाधिकारियों को समय अंतराल में कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश

स्वच्छता को अपनाकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं: किडो



शपथ ग्रहण करते छात्र-छात्राएं

KHUNTI : बिरसा कालेज खुंटी में राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता की शपथ ली। स्थापना दिवस पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। प्राचार्या प्रो. जी किड़ो ने छात्र-छात्राओं का आह्वान किया कि वे स्वंय साफ-सुथरा रहें और घर, कॉलेज, गांव सहित हर क्षेत्र में स्वच्छता को अपनायें। उन्होंने कहा कि सफाई

अपनाकर हम कई तरह की बीमरियों से बच सकते हैं। प्रोग्राम आफिसर डॉ पी सुरीन ने छात्र-छात्राओं को एनएसएस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ पी सुरीन, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो तारीफ लुगून, प्रो. पी तियू, राजकुमार गुप्ता, डॉ अभिषेक, प्रो. सावित्री, प्रो. इंदिरा, डॉ सिजरेन, प्रो. काली मुंडू, प्रो. अनीस, प्रो. निहाल, प्रो. सुजीत सहित सकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।















हाईकोर्ट से मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव व देवघर डीसी को अवमानना नोटिस

देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट क्यू कांप्लेक्स के फेज दो का निर्माण कार्ये शुरू नहीं होने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट की खंडपीट ने राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शॉ काज को रद्द कर दिया। जिसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सीएसआर फंड से देवघर में क्यू कंपलेक्स के फेज दो का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। जिस पर हाई कोर्ट की खंडपीट ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर डीसी को और अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन 10 माह बाद भी क्यों नहीं किया गया। उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर निर्धारित की है। दरअसल, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दिसंबर 2023 में

बाबा बैजनाथ मंदिर के निकट क्यू कांप्लेक्स निर्माण करने का मामला

- कोर्ट ने पूछा- आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ
- 16 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
- दिसंबर 2023 में निशिकांत दुबे की जनहित याचिका को स्वीकृत करते हुए निर्माण जल्द करने का दिया था आदेश



क्या था जनहित याचिका में

सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मंदिर, देवघर के लिए क्यू कंपलेक्स के दूसरे फेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अपने अंशदान के रूप में

लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। नवयुग कंपनी लिमिटेड कांप्लेक्स के द्वितीय फेज के निर्माण के लिए अपने स्तर से 120 करोड़ देने को

कंपनी के इस पत्र राज्य सरकार ने पहलें फेज का निर्माण परा हो चका है।

पहाडी मंदिर विकास समिति के मामले में मंदिर की नई कमेटी को झारखंड हाईकोर्ट ने किया मंग

डीसी की अध्यक्षता वाली पुरानी कमेटी को पुन: बहाल करने का निर्देश

RANCHI : पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग करने संबंधी झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से बनाई गई कमिटी को भंग कर दी है। साथ ही उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में बनी पुरानी कमेटी को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा पुरानी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया। प्रार्थी की और से कोर्ट को बताया गया कि पुरानी कमेटी को यह भंग करने का कोई कारण नहीं दिया गया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग करने के पूर्व बोर्ड से प्रस्ताव भी पारित नहीं कराया गया। बोर्ड के अध्यक्ष ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर समिति भंग करने का आदेश जारी किया है, जो गलत है। धार्मिक न्यास बोर्ड के पुरानी कमेटी को भंग करने का आदेश रद्द किया जाए। पूर्व में कोर्ट ने मामले में पहाड़ी मंदिर की 11 सदस्य वाली नई कमेटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर अदालत को

कमलेश के खिलाफ पीसी दाखिल RANCHI: कांके इलाके में लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने

कुमार के खिलाफ ईडी ने पीसी (प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) दाखिल कर दी है। मंगलवार को रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में एजेंसी ने पीसी दाखिल की है। जिसमें पूरे घोटाले की विस्तृत जानकारी दी गई है। ईडी द्वारा दायर पीसी पर कोर्ट जल्द संज्ञान ले सकता है। एजेंसी ने कमलेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें अहम खुलासे हुए थे। लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने जून महीने में कमलेश के घर पर छापेमारी की थी। जिसमें

उसके घर से एक करोड़ रुपए कैश और 100 कारतूस

बरामद हुए थे। ईडी की पूछताछ के बाद में कमलेश को

के आरोपी जमीन कारोबारी कमलेश

O BRIEF NEWS

निशिकांत दुबे की ओर जनहित याचिका

निर्माण जल्द करने का आदेश दिया था।

को स्वीकृत करते हुए देवघर में बाबा

बैजनाथँ मंदिर के क्यू कांप्लेक्स का

एसीबी के 101 आरक्षी व हवलदारों का तबादला

RANCHI : एसीबी में पदस्थापित 45 पुलिसकर्मी समेत १०१ आरक्षी और हवलदारों का तबादला हुआ है। डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी कार्मिक के द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, तबादला किए गए 101 पुलिसकर्मी में से 45 पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) में पदस्थापित थे। इसके अलावा धनबाद,बोकारो,सिमडेगा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रेल धनबाद, रेल जमशेदपुर, सरायकेला, देवघर, चाईबासा, चतरा, गढवा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले में पदस्थापित आरक्षी और हवलदार का तबादला किया गया है।

143 अंशकालिक शिक्षकों को सेवा अवधि विस्तार

RANCHI: राज्य के कल्याण विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को एक बार फिर सेवा अवधि विस्तार दिया गया है। इनकी सेवा ३१ मार्च २०२५ (एक साल) तक लिए जाने संबंधी संकल्प जारी किया गया है। बता दें कि इनका पूर्व का अवधि विस्तार मार्च में समाप्त हो गया था। विभाग ने कहा कि इस अवधि के बाद किसी परिस्थिति में अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा। इस बीच नियमित नियक्ति की प्रक्रिया की जायेगी। दरअसल, राज्यभर में आवासीय विद्यालय १० प्लस २. एकलव्य विद्यालय, आश्रम विद्यालय संचालित हैं। इनकी संख्या १४३ है। जिनमें स्वीकृत छात्रबल २५३४८ है। इन विद्यालयों में सुगम तरीके से पठन-पाउन हो इसके लिए अंशकालिक शिक्षकों की भी सेवाएं ली जा रही है। हर बार इनका अवधि विस्तार होता है। जबकि, इनके स्थान पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति होनी है। विभाग का कहना है कि तत्काल नयी बहाली कर पाना मुश्किल है। ऐसे में इस सत्र में पठन-पाठन प्रभावित न हो इसके लिए

राज्यभर के अमीन धरने पर, समान वेतन की मांग

आवश्यक है।

इनका सेवा अवधि विस्तार किया जाना

RANCHI : झारखंड राज्य के अमीन लोग अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैत गए हैं। झारखंड राज्य अमीन संघ के अध्यक्ष कंदन कमार और प्रदेश उपाध्यक्ष टेकलाल महतो ने कहा कि सरकार से लंबे समय से अपनी मांगों को कई माध्यमों से रख रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजबूरीवश उन्हें धरना पर बैठना पड़ा। इसके बाद भी बातें नहीं सुनी जायेगी तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

25 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है।

निर्णय नहीं लिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवघर में बाबा मंदिर के निकट क्यू कांप्लेक्स का निर्माण ३ फेज में किया जा रहा है। वर्ष 2011 में इसकी स्वीकृति दी गई थी। क्यू कंपलेक्स के

अब द्वितीय फेज का निर्माण कार्य परा होना है। देवघर बाबा मंदिर में दर्शन करने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्यू कांप्लेक्स बनने से श्रद्धालुओं को काफी राहत होगी। जन भावना को

दो दिनों में ईसीआई की टीम ने पूरी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा

इस बार के विस चुनाव में झारखंड के 2.59 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट

PHOTON NEWS RANCHI: मंगलवार को झारखंड में

विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दो दिनों तक भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्य टीम ने समीक्षा पूरी कर ली। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं उनकी टीम ने 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों की मांगों और आपत्तियों को सुना। फिर सरकार के आला अधिकारियों और चुनाव के दौरान काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक के बाद झारखंड निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2024 में 2.59 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 20 सितंबर 2024 तक झारखंड में 1.31 करोड परुष और 1.28 करोड महिला मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1.14 लाख वोटर हैं, तो 450 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में शामिल हैं।

आला अधिकारियों और चुनाव के दौरान काम करने वाली एजेंसियों को मिले कई निर्देश 85 साल से अधिक उम्र के 1.14 लाख वोटर, 450 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में दर्ज



राज्य के सभी प्रमंडलों के आयुक्त, जोनल आईजी, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करती ईसीआई की टीम

20 से 29 साल के 66.48 लाख वोटर

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स यानी 18 से 19 साल के 11.05 लाख मतदाता हैं। 66.48 लाख मतदाताओं की उम्र 20 से 29 साल के बीच है। 1,845 वोटरों की आयु 100 साल या उससे अधिक है। पीवीटीजी वोटर्स की संख्या 1.78 लाख है। कुल 3.64 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। झारखंड के मख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को विस्तार से जानकारी दी कि झारखंड में 20.276 जगहों पर 29,562 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। 5,042 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में

मतदान केंद्र पर औसतन

तरह से

का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयक्त ने चनाव आयोग को यह भी बताया कि 1,271 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं करेंगी। 139 बथ की जिम्मेदारी यवा मतदानकर्मियों को दी गई है। 48 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी मतदानकर्मियों को सौंपी गई है।

20276 जगहों पर बनाए जाएंगे 29562 मतदान केंद्र महिलाएं करेंगी १२७१ मतदान केंद्रों का संचालन रांची के रेडिशन ब्लू होटल में हुई बैठक में शामिल अधिकारी।

मतदान केंद्रों पर रहेंगी ये सविधाएं

- शौचालय
- मतदान केंद्र की जानकारी
- रैंप और व्हीलचेयर
- पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था

• वोटर सहायता केंद्र

म्री रेलवे स्टेशन से 31 बौतल शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा

एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।



PHOTON NEWS RANCHI:

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मुरी स्टेशन से एक व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज कुमार है। वह बिहार के पटना का रहने वाला है। इसके पास से 31 शराब की बोतल बरामद किए गए हैं। मुरी के आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने मंगलवार को बताया कि दुर्गा पजा के मद्देनजर रांची मंडल के आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के जरिये जांच के विशेष निर्देश मिले है। इसी क्रम मे आरपीएफ पोस्ट मुरी के साथ मे ऑपरेशन सतर्क अभियान के तहत गाड़ी संख्या 18626 की जांच की गयी। जांच के दौरान आरोपी ने मूरी स्टेशन से भागने का प्रयास किया लेकिन उसके सामान की जांच की गई। जांच के दौरान 31 शराब की बोतलें मिलीं। पछताछ में बताया कि वह शराब को लेकर बिहार में अधिक दाम पर बेचने के लिए ले जा रहा था।

ब्राउन शूगर की खरीद-बिक्री करते दो अरेस्ट

RANCHI: सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शूगर की खरीद-बिक्री करते दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सित्ती राम और अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों किशोरगंज के रहने वाला हैं। इनके पास से 16 पुडिया ब्राउन शुगर और

एक बाइक बरामद हुआ है। मंगलवार को डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि किशोरगंज रोड नंबर 05 के पास अवैध नशीले पदार्थों की खरीद बिर्क्र होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस टीम का गढन कर छापेमारी किया गया। पुलिस बल को देख भागने के क्रम में सित्ती राम और

अभिषेक यादव को पकड़ा गया।

ऑल इंडिया सब-जूनियर अंडर १३ बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप कल से

PHOTON NEWS RANCHI: रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर

विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑल इंडिया सब जुनियर अंडर 13 बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को रांची बैडमिंटन संघ ने प्रेस वार्ता पर प्रतियोगिता की जानकारी दी। झारखंड बैडमिंटन संघ के प्रभाकर राव, रांची जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष आरके मल्लिक, सचिव एनके डे ने मौके पर कहा कि इस प्रतियोगिता में देशभर के लगभग 400 बालक व बालिका भाग लेंगे। 26 और 27



सितंबर को प्रारंभिक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें एकल मुकाबले में टॉप 32 और युगल में टॉप 16 बालक और बालिका खिलाडियों को मेन डॉ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता के उद्घाटन में डीजीपी अनुराग गुप्ता और खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार रहेंगे। वहीं प्रतियोगिता के समापन समारोह में खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री दीपिका पांडे सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी।

जमीन घोटाले के आरोपी तलहा की बेल पर सुनवाई पुरी, आदेश सुरक्षित

RANCHI: धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष मामले के आरोपी तलहा खान की जमानत याचिका पर मंगलवार को ओर से बहुस पूरी सुनने के बाद खान ने जमानत के लिए हाई कोर्ट कर चुके हैं लेकिन दोनों ही कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार किया है।

न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग सुनवाई हुई। ईडी और बचाव पक्ष की अदालत ने जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तलहा की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। इससे पहले तलहा और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर

• हेल्पडेस्क

नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव ने साइट का किया निरीक्षण

ट्रांसपोर्ट नगर के उद्घाटन की तैयारी करें पूरी : सुनील

PHOTON NEWS RANCHI:

राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर का मख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्र यानि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में तैयार कर उद्घाटन कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर के साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने जुडको के अधिकारियों और एजेंसी केएमवी के प्रतिनिधियों निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हरहाल में ट्रांसपोर्ट नगर नवरात्र के



प्रथम सप्ताह में आम जनता और ट्रांसपोर्टरों को समर्पित कर दिया जाये। ट्रांसपोर्ट नगर के रखरखाव और संचालन की नीति एवं प्रक्रिया

जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाये, ताकि उद्घाटन के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में भारी, मध्यम और छोटे टुक लगने शुरू हो जाए

मई 2022 में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। अब तक एकीकृत भवन और दो वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तीन तलों में छोटे से लेकर बड़े वाहनों के खड़ा करने के तीन लेबल का प्लेटफार्म बनाने का काम पूरा हो गया है। सबसे खास बात यह है कि जो यहां पत्थर का गेवियन वाल बन रहा है, वह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसकी जोडाई में कहीं भी सीमेंट

का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

मई 2022 में रखी

गई थी आधारशिला

झारखंड में मेहरबान रहा मानसून, पांच जिलों को छोड़ पूरे राज्य में भरपूर बरसा पानी

धनबाद में इस साल सर्वाधिक बारिश, रांची में १६% अधिक

धनबाद में वर्ष 2024 में जमकर

बारिश हुई। 23 सितंबर तक

धनबाद में 30 प्रतिशत अधिक

बारिश हुई। अब तक धनबाद में

PHOTON NEWS RANCHI:

झारखंड में तीन साल के बाद सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 23 सितंबर तक झारखंड में 939.3 मिली मीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 4 प्रतिशत कम है। दिनों साइक्लोनिक सकुर्लेशन के कारण झारखंड के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि पांच जिलों में सामान्य से कम बारिश का आंकड़ा -20 से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, पाकुड़ में सबसे कम बारिश हुई है। 23 सितंबर तक पाकुड़ में 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। अब तक पाकुड़ में 552.4



मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य

बारिश 1134.4 मिमी है। वहीं

देवघर, चतरा, साहिबगंज में भी

सामान्य से कम बारिश हुई है।

साइक्लोन का असर, कुछ जिलों में 29 तक वर्षा की संभावना उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्से में RANCHI : बंगाल की खाडी में

बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र का असर राज्य में देखा जायेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दो साइक्लोन सक्रिय है। जिसका असर राज्य में देखा जायेगा। इससे २९ सितंबर तक राज्य में बारिश की जानकारी दी गयी है। इसमें 25 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। जबकि 26 और 27 सितंबर को राज्य के

बारिश की संभावना है। इसमें दुमका, गोड्डा, पाकुड़ साहेबगंज, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा समेत अन्य जिला शामिल है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गयी है। साइक्लोन के असर

1322.4 मिमी बारिश हुई है,

जबिक वहां 1016 मिमी सामान्य

बारिश है। वहीं राजधानी रांची में

सामान्य से 16 प्रतिशत अधिक

से राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी। जिससे अब धीरे-धीरे लोगों को सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होगा। हालांकि २९ सितंबर तक राज्य के कुछ जगहों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

बारिश हुई है। अब तक रांची में 1155.4 मिमी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में 28 सितंबर तक झारखंड में बारिश के आसार हैं।

साजिश का पता न चले इसलिए बंद करा दिया था इंटरनेट : बाबुलाल

RANCHI : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तल्ख कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुझसे मुलाकात की और परीक्षा में हुई साजिश से अवगत कराया। बांबूलाल ने ट्वीट में आगे लिखा है कि हेमते सरकार ने इस बार जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में चोरी कराने का नया तरीका इजाद किया और पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दी, ताकि किसी को इनकी साजिश का पता न चले। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि दरअसल, इस जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, वो पूर्व में हुई जेएसएससी–सीजीएल परीक्षा के प्रश्नों हुबहू मेल खा रहे हैं। 20 में 16 प्रश्न जेएसएससी-सीजीएल 2018-19 टियर 1 (7 जून 2019) से हूबहू मिलते पाए गए हैं।

माटी कला बोर्ड के जरिए शिल्पकारों के उत्थान का हो रहा प्रयास : भोक्ता



PHOTON NEWS RANCHI:

मंगलवार को मंत्री सत्यानन्द भोक्ता ने रांची स्थित मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड सभागार उद्योग भवन में झारखंड माटीकला के द्वारा आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला सह 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों के बीच कई आधुनिक

संयंत्र का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माटीकला बोर्ड के द्वारा शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं। माटीकला बोर्ड के माध्यम से शिल्पकारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़कर शिल्पकार अपने आय के स्रोत में वृद्धि कर

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घाटशिला मेन रोड किया जाम GHATSILA: घाटशिला मेन रोड काफी जर्जर हो गई है। इसकी मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया। कांग्रेस



(मनरेगा) जिला अध्यक्ष तापस चटर्जी के नेतृत्व में को घाटशिला मख्य सडक इतनी

जर्जर हो गई है कि इस पर पैदल चलना कठिन हो गया है।

डीसी ऑफिस के समक्ष धरना देगा भाजमो



बारीडीह स्थित विधानसभा कार्यालय में हुई, जिसमें विधायक सरयू राय भी

राजस्थान में सम्मानित किया

गया है। 15 सितंबर को नाथ

शहर में 'हिंदी लाओ देश बचाओ-2024' समारोह के

दौरान वहां की संस्था

सुबोध श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1अक्टूबर को जन समस्याओं पर डीसी ऑफिस के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसकी अगुवाई सरयू राय करेंगे।

तुलसी भवन के तीन साहित्यकार सम्मानित

JAMSHEDPUR : सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन और तुलसी भवन के तीन साहित्यकारों डॉ. ब्रजेंद्रनाथ मिश्र, डॉ. वीणा पांडेय भारती



साहित्य मंडल द्वारा हिंदी काव्य शिरोमणि की मानद उपाधि दी गई।

स्वच्छता के लिए चाईबासा में बनाई मानव श्रुंखला



से जिला समाहरणालय तक करीब ढाई किलोमीटर लंबी थी। अंत में कार्यपालक

अभियंता-पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा विनोद कुमार ने उपस्थित समृह को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

सुनील चंद्र ने लिया घाटशिला एसडीओ का प्रभार



ने मंगलवार को निवर्तमान एसडीओ सिच्चदानंद महतो से प्रभार ग्रहण किया। इस मौके पर अनुमंडल के कर्मियों ने नए अनुमंडल पदाधिकारी का स्वागत किया, 💌 📆 जबिक पुराने एसडीओ को विदाई दी।

जनसंख्या नियंत्रण कानून की रखी मांग

JAMSHEDPUR: भारतीय जन महासभा ने आश्विन कृष्ण सप्तमी (मंगलवार) को चतुर्थ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इसमें देश-विदेश के अनेक लोग ऑनलाइन जुड़े। संस्था के अध्यक्ष धर्म चंद्र पोद्दार ने स्वागत भाषण में उल्लेख किया कि देशहित में आवश्यक है कि

दशहरे से पहले कंपनियों में बोनस की बहार, खिले चेहरे



समझौता पत्र दिखाते कंपनी व यूनियन के पदाधिकारी

JAMSHEDPUR : टाटा स्टील के वायर डिविजन (तार कंपनी व जेम्को) के कर्मचारियों का बोनस समझौता मंगलवार को हो गया। कर्मचारियों को इस बार 14.5 प्रतिशत बोनस मिलेगा, जिसमें 540 कर्मचारियों के बीच 2.22 करोड़ रुपये का वितरण किया कर्मचारियों अधिकतम 64 हजार और न्युनतम 16,500 रुपये मिलेंगे। समझौते पर प्रबंधन की ओर से ईआईसी-

जीडब्ल्युआई अनुराग पांडे, सीओओ-जीडब्ल्यूआई सतीश वालेकर, एचआरबीपी-कमर्शियल एंड पीसी की चीफ किंकनी दास. हेड ऑपरेशन जेके सिंह, फाइनेंस हेड उमानाथ मिश्रा, विजयंत कुमार, एचआर हेड शिल्पी शिवांगी ने हस्ताक्षर किया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, डिप्टी प्रेसीडेंट श्रीकांत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट दानी शंकर तिवारी, मनजीत सिंह आदि थे।

टाटा स्टील के वायर डिविजन में | टिमकेन के कर्मचारियों को | जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मियों मिलेगा १९.७५ प्रतिशत बोनस



बोनस समझौते के दौरान उपस्थित प्रबंधन व यूनियन के पदाधिकारी

JAMSHEDPUR : टिमकेन इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर प्लांट का बोनस समझौता मंगलवार को हो गया। 200 कर्मचारियों के बोनस के लिए टिमकेन वर्कर्स यूनियन एवं प्रबंधन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कर्मचारियों को 19.75 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 1.40 लाख और न्यूनतम 95000 रुपये मिलेंगे। बोनस की राशि सितंबर की सैलरी के साथ कर्मचारियों के

समझौते पर प्रबंधन से जनरल मैनेजर प्लांट ऑपरेशन राजीव शाश्वत, जीएम एचआर दिनेश सिंह, एजीएम हिमांशु मिश्रा, प्लांट कंट्रोलर रूपेंदु बनर्जी, डीएम नितेंद्र भटनागर, यूनियन से अध्यक्ष आस्तिक महतो, महामंत्री विजय यादव, डिप्टी प्रेसिडेंट अनिल पांडे, रविंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, सुधीर कुमार राय, शुभाशीष

को मिलेंगे १,९८,४९४ रुपये



बोनस समझौते के बाद प्रबंधन का अभिवादन करते राकेश्वर पांडेय 🏻 फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR विस्टास कॉर्प लिमिटेड, जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों के लिए मंगलवार को बोनस समझौता हो गया। कर्मचारियों को 17.5 प्रतिशत बोनस मिलेगा। इसके तहत न्यूनतम 82,075 रुपये व अधिकतम 1,98,494 रुपये मिलेंगे। औसतन बोनस की राशि 1,40,852 रुपये मिलेगी। बोनस राशि एक सप्ताह में कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। समझौते पर

प्रबंधन की ओर से न्यवोको प्रबंधन के क्लस्टर हेड बी. उमा सर्यम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (एचआर) संदीप पांडे, जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के एचआर हेड सोहेल खान, वरीय प्रबंधक (आईआर) समीर कुमार एवं सोनिक सिंह और युनियन से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, महासचिव बिजय खां आदि ने हस्ताक्षर किए।

बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का दम सिर्फ भाजपा में : चम्पाई सोरेन

भाजपा की कोल्हान प्रमंडल संकल्प यात्रा के तहत पोटका में हुई सभा

PHOTON NEWS JSR:

भाजपा की कोल्हान प्रमंडल में चल रही परिवर्तन यात्रा मंगलवार को पोटका विधानसभा पहुंची। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत पोटका विधानसभा क्षेत्र के जुड़ी गांव स्थित स्टेडियम मैदान में विशाल परिवर्तन सभा हुई।

जनसभा को संबोधित करते हुए चम्पाई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में ही वो दम है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर झारखंड की संस्कृति, सभ्यता के साथ जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रख सकती है। आज पूरे राज्य मे परिवर्तन जरूरी है और जनसभा में उमड़ी जनता की भीड़ का संदेश है कि अब परिवर्तन के मूड में हैं।झारखंड के लिए संघर्ष एवं आंदोलन के पश्चात भाजपा ने ही



झारखंड को सजाने एवं संवारने का काम किया है। राज्य का संपूर्ण विकास भाजपा ही कर सकती है। संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची मे शामिल करने का काम भाजपा ने किया है। कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी-मूलवासी की हितैषी नहीं रही है। कांग्रेस के शासन में आदिवासी एवं मलवासी समाज

आज झारखंड के संथाल परगना समेत कोल्हान क्षेत्र मे बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी समस्या बन गई है,

अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जन मुंडा ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार की लूट, झूठ और वादाखिलाफी से झारखंड की

जनता हताश और निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ अपने परिवार को आदिवासी समाज मानते हैं और किसी अन्य आदिवासी नेता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जनजातीय समाज की बातें करने वाले हेमंत सोरेन झारखंड और झारखंडवासियों के लिए संघर्ष करने वाले जनजातीय

GHATSILA : भाजपा का

परिवर्तन यात्रा रथ मंगलवार को

पोटका रवाना हुआ। इससे पूर्व

परिवर्तन यात्रा के कोल्हान प्रभारी

पत्रकारों से कहा कि परिवर्तन

यात्रा में हर वर्ग का समर्थन मिल

पुरे कोल्हान में भाजपा लहराएगी परचम : गोस्वामी

शामिल हो रहे हैं। कोल्हान की सभी 14 सीट पर भाजपा परचम लहराएगी। इस मौके

पर जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साव, रविशंकर सिंह,

सुनीता देवदूत सोरेन, गीता मुर्मू, देवयानी मुर्मू, दीपक दंडपात आदि उपस्थित थे।

हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि थे। आखिर,क्यों उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई। यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वीरों की धरती को बेचने के लिए ही झारखंड अलग राज्य बना था।

पेड़ पर लटका मिला लापता युवक का शव हत्या की आशंका

SARAIKELA : सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत डुमरा पंचायत के जंगलीबाद जंगल में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पेड़ पर लटका पाया गया। मृतक की पहचान समीर मंडल के रुप में की गई। समीर रविवार शाम से ही लापता था। इधर, मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में लालटू महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कांड्रा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि समीर गुजरात में काम करता था। बीते दिनों ही वह घर आया था। परिजनों के अनुसार 1 सितंबर को समीर गांव के ही लालटू महतो के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बसह हो गई थी। उस वक्त लालट् ने समीर को जान से मारने की भी धमकी दी थी। रविवार शाम से ही समीर लापता हो गया। उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मंगलवार की सुबह समीर का शव घर से

परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कॉलेज शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे

कार्रवाई की मांग को लेकर आज सामृहिक अवकाश पर रहेंगे टाकू से जुड़े शिक्षक

PHOTON NEWS JSR:

कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अजय कुमार चौधरी व टीचर एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी (टाकू) के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार के बीच सोमवार को हुए विवाद के विरोध में मंगलवार को टाकू से जुड़े शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इसके साथ ही संगठन की ऑनलाईन बैठक में तय हुआ नियंत्रक व्यवहार खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर अपने प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने का निर्णय लिया गया। टाकू के सभी सदस्यों ने एक सुर में इस अप्रिय



नारेबाजी करते कॉलेज के शिक्षक

घटना की निंदा एवं भर्त्सना की। संघ के पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा किए बदसलकी और उसके कारनामों के बारे में कलाधिपति. कुलपति एवं शिक्षा मंत्री को शिकायत की जाएगी एवं उसे • फोटोन न्यूज

पदमुक्त कर शिक्षकों और विश्वविद्यालय के सम्मान रक्षा करने की अपील करते हुए संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन की

टाक की बैठक में तय किया गया बुधवार को कोल्हान विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी शिक्षक मुख्यालय पहुंच कर प्रदर्शन करते हुए परीक्षा नियंत्रक को पदमुक्त करते हुए दंडात्मक

कार्रवाई की मांग करेंगे। संघ की ओर से इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज का कोई पदाधिकारी किसी शिक्षक के खिलाफ अपमानजनक भाषा बोलने या उत्पीड़न करने का साहस नहीं करें। इस दौरान संघ से जुड़े सभी शिक्षक सामृहिक अवकाश में रहेंगे। वहीं, इस पूरे विवाद पर केयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अजय कुमार चौधरी दूसरे दिन भी मुखर रहे। उन्होंने कहा कि लगता है कि टाकू परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की सुपारी ले रखा है। यही वजह है कि विवि व छात्रों की दूसरी समस्या को छोड़ परीक्षा नियंत्रक

पर निजी हमला कर रहा है।

दीर्घकालिक उत्पाद रणनीतियाँ

तृतीय सत्र में लंबे समय के लिए उत्पाद रणनीतियों की आवश्यकता को

हो। वक्ताओं ने कहा कि बदलते बाजार और ग्राहक अपेक्षाओं के साथ

अनुकूल होने के लिए लचीली और भविष्य तैयार उत्पाद रणनीतियों की

मैनेजमेंट प्रवीण कुमार, पे पल के रामप्रसाद सुब्बुरामन, निलसेल्क के

लैब्स के सौरव कुमार ने किया। उन्होंने ग्राहक व्यवहार में बदलती

आवश्यकता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट

प्रोडक्ट लीडरशिप डायरेक्टर वीरेंद्र नाडगीर, यूकेजी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट

डायरेक्टर अंकुर बंसल ने अपे विचार रखे। पैनल का समापन अमेडियस

गतिशीलता पर चर्चा की और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए

उँजागर किया गया, जो बदलते बाजारों और ग्राहक अपेक्षाओं के अनुकूल

मानगो में फंदे पर लटकी मिली युवक की लाश

JAMSHEDPUR : मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर के रोड नंबर 13 निवासी शहनवाज आलम उर्फ मोंटी (18) की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली। घटना सोमवार शाम की है। परिजनों ने शहनवाज को फंदे से लटका पाया, जिसके बाद उसे फंदे से उतारकर टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में शहनवाज के पिता महमूद आलम के बयान पर अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि शहनवाज पूर्व में बाइक चोरी के आरोप में बाल सधार गह जा चका था इसके अलावा उस पर छेड़खानी का भी एक मामला दर्ज है। पिता के अनुसार शहनवाज नशे का आदी था। सोमवार को वह रुपये की मांग कर रहा था। रुपये नहीं देने पर उसने फांसी लगाकर

जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू

टी-शर्ट का लोकार्पण करते डीडीसी JAMSHEDPUR : पर्वी सिंहभम जिले में 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त यवा अभियान प्रारंभ किया गया है। समाहरणालय से मंगलवार को उपविकास आयुक्त मनीष कुमार ने जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है और जिला तथा प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उपविकास आयुक्त ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य यवाओं में जागरूकता फैलाना है। सभी की भागीदारी



CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला में तंबाकू मुक्त युवा अभियान-2.0 शुरू किया गया, जो 24 सितंबर से 23 नवंबर तक चलेगा । सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो मांझी की अध्यक्षता में मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय के सभागार में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जिला नोडल पदाधिकारी एनसीडी डॉ. मीना, उपाधीक्षक सदर अस्पताल

डॉ. शिव चरण हांसदा, डॉ. भारती मिंज, डॉ. मीना,

प्रधानाद्यापिकाशिल्पा गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

आवश्यक है, विशेष रूप से स्कल, मेडिकल एजकेशन और पंचायती राज संस्थाओं का योगदान महत्वपर्ण होगा। उन्होंने जोर दिया कि जिले के प्रत्येक युवा और नागरिक को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रह जाए।

इस दौरान, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, धालभूम शताब्दी सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल और अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और गब्बारे उडाकर नशामक्ति का

एक्सएलआरआई में उत्पाद संगोष्टी ऑरोरा २.० आयोजित, कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा-

उत्पाद, विकास, नवाचार को बढ़ावा दे रहा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस

PHOTON NEWS JSR:

एक्सएलआरआई-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 23 सितंबर को प्रॉडजोन क्लब की द्वितीय उत्पाद संगोष्ठी ऑरोरा 2.0 का आयोजन किया गया। पीजीडीएम (जीएम) 2024-25 बैच के छात्रों की ओ? से हुई संगोष्ठी का विषय था 'भविष्य की दिशा : डिजिटल युग में उत्पाद विकास का नेतृत्व'। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के महत्व पर वक्ताओं ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआई उत्पाद विकास में क्रांति ला रहा है। डेटा विसंगतियों को कम कर रहा है, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार कर रहा है और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इस सत्र में डनहुम्बी के ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट यश पिपलानी, नाइकी इंडिया



टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रोडक्ट डायरेक्टर मोनार्क हिमांशु, एयरटेल डिजिटल के प्रोडक्ट हेड थुलसी चंद्र पामुजुला तथा इंडमनी के प्रोडक्ट डायरेक्टर ऋत्विक रॉय ने अपने विचार रखे। द्वितीय सत्र डिजिटल उत्पादों के मुद्रीकरण पर वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल उत्पादों का मुद्रीकरण मार्केट फिट की पहचान करने और स्पष्ट

राजस्व लक्ष्य निर्धारित करने तथा नए राजस्व स्रोतों को खोलने की कुंजी है। इसमें सेल्सफोर्स की प्रोडक्ट डायरेक्टर श्वेता कौशिक सिन्हा, एक्सिस बैंक के वीपी सह हेड अभिजीत डे, प्रियरंजन अटलासियन के सीनियर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर मोइनाक चटर्जी,

निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता पर वल दिया।

इन्फोगेन के डायरेक्टर गौरव गुप्ता ने अपने विचार रखे। इस पैनल ने उपस्थित वक्ताओं ने ग्राहक आवश्यकताओं और उद्योग प्रवृत्तियों को सरेखित करते हुए राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान की। इससे पूर्व एक्सएलआरआई के निदेशक फादर जॉर्ज एसजे, प्रो संजय पात्रो, फादर डोनाल्ड

डी'सिल्वा, फादर कुरुविला, प्रो कनगराज, प्रो सुनील सारंगी समेत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी की शुरूआत की। इसके पाद प्रथम सत्र आरंभ हुआ। इसमें इस विषय पर चर्चा हुई कि एआई उत्पाद विकास में किस तरह से क्रांति ला रही है तथा नवाचार को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है।

कस्टमर कंपास : युजर-सेंट्रिक अंतर्दृष्टियां

अंतिम सत्र 'कस्टमर कंपासः यूजर–सेंट्रिक अंतर्दृष्टियों के साथ उत्पाद विकास को नेविगेट करना ने व्यवसाय लक्ष्यों को ग्राहक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने पर गहन अंतर्दृष्टियां प्रदान कीं। इसमें पैनलिस्ट के रूप में सर्विस नाऊ की प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर जननी जयरामन ने बताया कि सीखने के चरण को संकीर्ण करना और ग्राहक फीडबैक के आधार पर उत्पाद सुविधाओं को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि बाजार की मांगों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके। इनके अलावा यूलू के हेड ऑफ प्रोडक्ट संदील्या कोंडुरी, पेटीएम के प्रोडक्ट डायरेक्टर सिद्धांत दल्वी, एयरटेल के के प्रोडक्ट वीपी प्रभात कुमार ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की उजागर किया।

विधायक ने किया ११ करोड़ की तीन योजनाओं का शिलान्यास



बंदगांव में महिलाओं के साथ विधायक सुखराम उरांव

BANDGAON : चकधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने मंगलवार को बंदगांव प्रखंड में 11 करोड़ 23 लाख रुपये की तीन योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रखंड के नकटी पंचायत के इंदरूवा में 4 करोड़ 20 लाख रुपये और हुडागंदा पंचायत के परसाबहाल नदी पर 5 करोड़ 3 लाख रुपये से पुल और कराईकेला प्लस टू उच्च विद्यालय में लगभग 2 करोड़ की लागत से 17 कमरा वाला भवन बनेगा। इससे पहले विधायक का ग्रामीणों ने गाजे-बाजे

के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कराईकेला प्लस टू उच्च विद्यालय के छात्रों में साइकिल वितरण किया। इंदरूवा नदी पर पुल बनने से बंदगांव, सोनुवा व गुदड़ी प्रखंड के हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल के लिए ग्रामीण 30 साल से मांग कर रहे थे। कई बार सांसद-विधायक से गुहार लगाई गई। इस मौके पर प्रमुख पीटर घनश्याम तियु समेत कराईकेला प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षक व छात्र मौजुद थे।



कार्डियोलॉजिस्ट बनकर रखें लोगों के दिलों का ख्याल

एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया कुरने, आत्म-प्रेरित होने और चिंकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का एक बैहृद म्हत्वपूर्ण आंतरिक अंग है और एके हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जरूरी है कि आप इसका पूरी तरह ख्याल रंखें।

आमतौर पर लोग अपने दिल का ख्याल रखने के लिए खानपान से लेकर अन्य कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ती है। कार्डियोलॉजी चिकित्सा का एक प्रभाग है जो हृदय विकारों से संबंधित निदान और उपचार से संबंधित है। दिल के विकारों से निपटने वाले चिकित्सा चिकित्सकों को आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की इस शाखा का बेहद महत्व है और अगर आप चाहें तो इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं-

क्या होता है काम

एक हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय, धमनियों और नसों का डाँक्टर है।एक्सपर्ट्स के अनुसार, हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की विफलता, जन्मजात् हृदय दोष और कोरोनरी धमनी रोग का निदान और उपचार प्रदान करते हैं। इसमें धमनियों के संकीर्ण होने, हृदय के वाल्व में समस्याएं, मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान और पेरिकार्डियम के विकार के कारण प्रतिबंधित परिसंचरण के कारण होने वाली समस्याएं शामिल हैं।

रिकल्स

एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के पास ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान में संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोगियों की सेवा करने, दूसरों के प्रति दया करने, आत्म-प्रेरित होने और

चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए अनुशासन, धैर्य, उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास का होना भी उतना ही आवश्यक है। उनके पास जीवन की खतरनाक स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कैरियर कोच कहते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ को भी आहार और व्यायाम विशेषज्ञ भी होना चाहिए।

योग्यता

एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री के अलावा कई सालों की प्रैक्टिस, लाइसेंस व बोर्ड सर्टिंफिकेशन होना चाहिए।कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एमडी/एमएस या डीएनबी की डिग्री लेने के बाद इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन के लिए डीएम इन कार्डियोलॉजी की डिग्री लेनी होगी। इस डिग्री की अवधि लगभग तीन साल की होती है ।

अवसर

कॅरियर काउंसलर के अनुसार, एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आप सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में बतौर डॉक्टर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्डियक रिहैबिलेशन सेंटर या क्लीनिक टेस्टिंग सेंटर्स में भी काम कर सकते हैं।वहीं आप खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं और खुद का क्लीनिक खोल सकते हैं।जो कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ाना पसंद करते हैं, वे मेडिकल कॉलेजों में बतौर लेक्चरर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

आमदनी

एक कार्डियोलॉजिस्ट की आमदनी उसके अनुभव व भौगोलिक स्थान पर मुख्य रूप से निर्धारित होती है।जो कार्डियोलॉजिस्ट शहर में काम करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सैलरी मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी का स्तर कम हो सकता है।हालांकि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में बतौर फ्रेशर काम शुरू करते हैं, तब भी शुरूआती दौर में आप 25000 रूपए आसानी से कमा सकते हैं। जबिक निजी अस्पतालों में वेतन अधिक हो सकता है। वहीं कुछ वर्षों के अनुभव के बाद आपकी आमदनी लाखों में हो सकती है।

प्रमुख संस्थान

- गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली
- रविन्द्रनाथ टैंगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डिंयक साइंस, कोलकाता
- मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली
- आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे
- संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ



फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कॅरियर कैसे बनाएं ? कोर्स, जॉब और सैलरी

फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं।फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्टस टेक्नोलॉजी का डस्तेमाल करके क्राइम स्पॉट पर मौजूद संबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकडने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल आपराधिक मामलों की जांच और कानुनी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में केमिस्टी, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलोजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग आदि फील्ड्स शामिल होती हैं। इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्टस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके

देशों से हायर एजुकेशन

टू-डू लिस्ट में शामिल

कर लेते हैं और कई लोग इसे प्राप्त

करने से वंचित भी रह जाते हैं।

विदेशों से हायर एजुकेशन की

पढाई करने पर जीवन में कई

अवसर मिलते हैं । हालांकि हायर

एजुकेशन जितने बेहतर अवसर

देता है उतना ही खर्चीला भी है।

विदेशों में पढ़ाई करने के लिए एक

बेहतर प्लानिंग की आवश्यकता

तो होते ही है साथ ही आवश्यकता

होती है नॉलेज की । उसी नॉलेज

और प्लानिंग में से एक है

स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई

करना । जब स्कॉलरशिप की बात

आती है तो हमें कई बातों को ध्यान

में रखना पड़ता है।आइए जानते हैं

कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें

स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएं

हालांकि स्कॉलरशिप के लिए

एकेडमिक स्ट्रेन्थ आवश्यक है ।

अधिक है तो स्कोर बेहतर माना

जाता है । लेकिन केवल इतना ही

लिए अप्लाई करते वक्त इस बात

बेहद स्ट्रांग होना चाहिए । इसके

आवश्यक नहीं है। स्कॉलरशिप के

का ध्यान रखें कि आपका प्रोफाइल

लिए आप इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम

एक्टिवटी जैसे स्पोर्टस, म्यूजिक,

लिखें । इससे आपका प्रोफाइल बेहद

ड्रामा इत्यादि की डिटेल जरूर

स्ट्रांग बनेगा।

अगर मास्टर्स करने का आप प्लान

बना रहे हैं तो आपका जीपीए 70 से

ध्यान में रखना पड़ता है।

स्कॉलरशिप प्राप्त करने से पहले

प्राप्त करना कई लोगों की

होता है । कई लोग इसे प्राप्त

क्राइम स्पॉट पर मौजूद सबूतों की जाँच करते हैं और अपराधियों को पकडने में मदद करते हैं। इसके लिए वे क्राइम सीन, ब्लड सेंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग आदि की जांच करते हैं।

कोर्स

फॉरेंसिक साइंस में करियर बनाने के लिए 12प्द्ध में साइंस होनी जरूरी है। आप फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ में एक वर्षीय डिप्लोमा कर सकते हैं।आप फॉरेंसिक साइंस 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी भी कर सकते हैं।इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन और रिसर्च करने के इच्छुक हों तो फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को जिज्ञासु होना चाहिए और साहसिक कार्यों में दिलचस्पी होनी चाहिए। इस फील्ड में हर कदम पर चुनौती है इसलिए आपको दिमागी तौर पर मजबूत होना जरूर है। इसके साथ ही आपके अंदर मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स होना भी बेहद् जरूरी है।एक फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को कई तरह की

टेस्ट रिपोर्ट लिखनी होती हैं इसलिए आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ।फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट को सबूतों की जाँच करनी होती है इसलिए आपको एकाग्रता और सतर्कता के साथ काम करना आना चाहिए।

कहां मिलेगी नौकरी

इस फील्ड में सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की भरमार है। फॉरेंसिक साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद आपको पुलिस, लीगल सिस्टम, इंवेस्टिगेटिव सर्विंस जैसी जगहों पर जॉब मिल सकती है। वहीं, कोई प्राइवेट एजेंसी भी आपको बतौर फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स जॉब ऑफर कर सकती है। अगर आप में योग्यता है तो आपको फॉरेंसिक साइंटिस्ट इंटेलि?जेंस ब्यूरो और सीबीआई में भी नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है । इसके अलावा आप किसी फॉरेंसिक साइंस शिक्षण संस्थान में टीचर के रूप पढ़ा कर अच्छी सैलरी कमा सकते हैं।

सैलरी

योग्यता के आधार पर आपको शुरुआत में 20-50 हजार रुपये प्रतिमाह तक सैलरी मिल सकती है। समय के साथ अनुभव होने पर आप 6 से 8 लाख रुपये तक महीना कमा सकते हैं।



विदेशों में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप

से आगे बढ़कर सोचें ध्यान रखें कि विदेशों में पढ़ने के लिए केवल यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि कई संस्था स्कॉलरशिप प्रदान करती है। ये स्कॉलरशिप सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी दिया जाता है। अगर आप भारत में हैं तो कईं संस्था जैसे टाटा आपको विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी । इसके साथ ही अगर आप विदेश में हैं तो वो देश भी विदेशों छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप प्लान पर कार्य करता है। इन स्कॉलरशिप के बारे में दोनें देशों के एजुकेशन डिपार्टमेंट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कोर्स से पहले कर दें अप्लाई

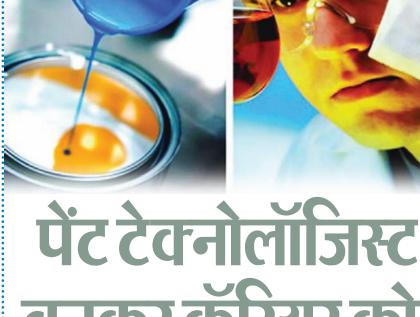
आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके शुरू होने से 18 महीने पहले आप अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दें । ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदन करने के बाद डॉक्यूमेंट सबिमशन और वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता है।ऐसे में आपको समय पर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और कोर्स में भी कोई समस्या नहीं होगी।

एप्लीकेशन का कराएं रिव्यू

एप्लीकेशन फॉर्मे भरने के बाद यह सबसे बेहतर आइडिया है कि उसका रिव्यू करा लिया जाए। रिव्यू कराने से एप्लीकेशन की कमियां सामने आएगी और उसके बाद सुधार किया जा सकेगा। अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लें और उसे किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं।ये प्रोफेशनल आपके शिक्षक या कोई अन्य एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। इससे आपको रिव्यू मिलेगा और आप एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे ।

अधिक से अधिक रियल रहने का प्रयास करें

जब एप्लीकेशन लिखे तो ज्यादा से ज्यादा रियल रहने का प्रयास करें। यूनिवर्सिटी में आप खुद को निखारने और खुद को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं इसी कारण एप्लीकेशन में ख़ुद को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर ना लिखें।जो हैं वह ईमानदारी के साथ लिखें और अपने स्किल, पैशन और इंटरेस्ट आदि के विषय में लिखें।



बनकर कॅरियर को दें एक रंगीन दिशा

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग-अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मुल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिंस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है। रंगों का जीवन से एक गहरा नाता है। रंगों के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कपडों से लेकर घर तक हर जगह तरह-तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इन्हीं रंगों में अपना करियर बनाने की सोची है। अगर नहीं, तो अब आप इस क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। जी हां, पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा ही क्षेत्र है। अगर आप भी चाहें तो इस क्षेत्र में अपना सफल भविष्य बना सकते हैं।तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में

क्या है पेंट टेक्नोलॉजी

पेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न इंग्रीडिएंट जैसे रॉल, पॉलिमर व पिगमेंट आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। पेंट टेक्नोलॉजी में, विभिन्न प्रकार के पेंट, उनके निर्माण, विभिन्न प्रकार के पेंट के उपयोग और पेंट के अनुप्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस विषय क्षेत्र में स्नातक करने वालों को पेंट टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है।

क्या होता है काम

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट अलग–अलग एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पेंट की उपयुक्तता की पहचान और मूल्यांकन करता है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहकों को पेंट के सही उपयोग के बारे में समझाता है और उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करता है । उनके काम में पेंट के नए रंग और बनावट विकसित करना,

पेंट एप्लीकेशन के लिए नई तकनीक को विकसित करना आदि शामिल हैं। सरल भाषा में, वे नए उत्पादों को विकसित करने के साथ-साथ उन उत्पादों के गुणों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए जिम्मेदार हैं जो पहले से ही विकसित किए गए हैं।

पर्सनल स्किल्स

एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को रंगों से बेहद प्यार होना चाहिए। साथ ही उसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी होने चाहिए, ताकि वह नए रंगों के साथ-साथ उनके टेक्टचर को भी बेहतर बना सके । एक पेंट टेक्नोलॉजिस्ट को मेहनती होना चाहिए। इसके अलावा, आपमें अच्छी संचार कौशल और टीम भावना होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस उद्योग में अन्य पेशेवरों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही विभिन्न विभागों में टीमों का नेतृत्व करने के लिए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट में प्रबंधकीय कौशल भी आवश्यक है।

योग्यता

इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको बीटेक इन पेंट टेक्नोलॉजी करना होगा।बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं।अधिकाश संस्थानों द्वारा पेंट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को केमिकल इंजीनियरिंग में एक विषय के रूप में भी पेश किया जाता है

संभावनाएं

पेंट उद्योग के विभिन्न विभागों में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। वे पेंट निर्माण कंपनियों के किसी भी विभाग में काम पा सकते हैं । पेट उद्योग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट उद्योग पर निर्भर है ।कई बड़ी–बड़ी पेंट मैन्युफैक्चिरिंग कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड, शालीमार पेंट्स, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड आदि में पेंट टेक्नोलॉजिस्ट की हमेशा ही जरूरत होती है। पेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, होम फर्निशिंग इंडस्ट्री आदि में भी कार्य कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में वेतन आपके अनुभव और उस सेक्टर पर निर्भर करता है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत करने वाले व्यक्ति प्रारंभ में 1,25000 रूपए से 2,00000 रूपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है । वहीं, अनुभव बढने के साथ–साथ आपका वेतन भी बढ़ता जाता है।

प्रमुख संस्थान

हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जलगांव, महाराष्ट्र गार्वेयर इंस्टीट्यूट् ऑफ कॅरियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सांताक्रूज, महाराष्ट्र लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर



से व्यवहार करना चाहिए। वकील

कुर्ता-पायजामा या शॉट्र्स-टी-शर्ट

पहन कर बहस नहीं कर सकते।

वकीलों को यह समझना चाहिए

कि उनकी वेशभूषा उनके पेशेवर

आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा

है। इसका मतलब यह है कि

अदालतें वकीलों के लिए निश्चित

स्तर की पेशेवरता की अपेक्षा

करती हैं, जिससे अदालत की

गरिमा बनी रहे। आप कह सकते

हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय

स्पष्ट करता है कि वकीलों के लिए

पेशेवरता और गरिमा का पालन

आवश्यक है। यह न केवल उनके

व्यक्तिगत चित्रण को दशार्ता है,

बल्कि यह अदालत की छवि और

उसकी गंभीरता को भी बनाए

रखता है। अब उच्चतम न्यायालय

के आए इस निर्णय की तुलना

कोर्ट के पिछले माह दिए गए

निर्णय से करते हैं, बात वहां भी

ड्रेस कोड की ही थी, किंतु यही

न्यायाधीशों के निर्णय ने जैसे एक

समाज को ही कटघरे में खड़ा कर

दिया था। कहना होगा कि नौ

अगस्त को आए एक निर्णय में

आज फिर से एक बार उच्चतम

न्यायालय के निर्णय पर विचार

माननीय सुप्रीम कोर्ट

कैसे पैदा होंगे बिना राजनीतिक विरासत वाले युवा नेता

आज देश को ऐसे युवा नेताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आते। भारत को वंशवादी राजनीति से मुक्त होने की जरूरत है। राजनीति और शासन में युवाओं की भूमिका है, विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक जीवन में भाई-भतीजावाद और वंशवादी उत्तराधिकार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में। ऐतिहासिक रूप से युवा नेतृत्व उद्योग और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। युवा नेता अक्सर नवाचार के मामले में सबसे आगे रहे हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में, जहां उनके योगदान ने उद्योगों में क्रांति ला दी है। भारत में, जहां आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है. 18वीं लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की औसत आयु 56 वर्ष है, जो युवा जनसांख्यिकी और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच एक महत्वपूर्ण वियोग को उजागर करती है। भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत बनाने के लिए अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की राजनीति को युवा देश, बुढ़े नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले ज्यादातर युवा नेता बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जो सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं। हालांकि मुख्यधारा की लगभग हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्टूडेंट विंग है और ये सभी पार्टियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों में जोर-शोर से भाग लेती हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है, जो छात्र नेताओं को विधायी राजनीति में आगे बढ़ने में मदद कर सके और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, 17वीं लोकसभा (2019-2024) में 40 वर्ष के कम उम्र के सांसदों की संख्या महज 12 प्रतिशत है, वहीं स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में 26 प्रतिशत सांसदों की उम्र 40 वर्ष से कम थी। हर बड़े चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्रों में युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों शुरू करने की बात करती हैं, जिनका अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए भारी प्रचार किया जाता है। राजनीतिक संपर्क अभियानों में बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल किया जाता है और राजनीतिक पार्टियां शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनावी रैलियों में युवाओं की भागीदारी को प्रचारित करती हैं। हालांकि चुनाव के बाद युवाओं के मुद्दे (शिक्षा और रोजगार) को तरजीह नहीं दी जाती, जो चुनावी राजनीति में युवाओं की कमजोर स्थिति को बताता है, क्योंकि उनमें अपनी मांगों को मजबूती से रखने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि छात्र नेता जब विधायी चुनावों में शामिल होते हैं, तो उनके पास राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत बेहद सीमित होती है। इस तरह से देखें तो यही लगता है कि युवाओं की मतदाता भागीदारी अगर कम है, तो यह एक विचित्र घटना न होकर एक अपेक्षित परिणाम मात्र है। भाई-भतीजावाद और वंशवादी राजनीति युवा नेताओं के लिए बड़ी बाधा बनकर आती है। ये जड़ जमाए हुए सिस्टम उभरते नेताओं के लिए दृश्यता और प्रभाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों, अवसरों और प्लेटफार्मों तक पहुंच को सीमित करते हैं। आज देश में बिना किसी राजनीतिक विरासत के 1 लाख युवाओं के राजनीति में प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए इन युवाओं के लिए सही अवसर, मार्गदर्शन और सहायता प्रणाली प्रदान करना आवश्यक है। युवा नेताओं को अधिक समावेशी बनाने के लिए राजनीतिक संस्कृति को बदलने से स्थापित राजनीतिक वर्ग और मतदाताओं दोनों के भीतर मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। यह परिवर्तन नेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो शासन में नए दृष्टिकोण और अभिनव समाधान ला सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्रों में युवा नेताओं ने गहरा प्रभाव डाला है। लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क जैसे लोगों ने कम उम्र में परे उद्योगों में क्रांति ला दी है। युवा पेशेवरों के वर्चस्व वाले भारत में आईटी उद्योग ने देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ और वैश्विक मान्यता दिलाई है। इसके विपरीत बड़ी युवा आबादी के बावजूद राजनीतिक परिदृश्य यवा प्रतिनिधित्व में काफी पीछे है। यह असमानता एक महत्वपर्ण क्षेत्र को उजागर करती है, जहां राजनीतिक नेतत्व को राष्ट्र की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के साथ सरेखित करने के लिए सधार आवश्यक है। विभिन्न सरकारी पहलों का उद्देश्य शासन में यवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जैसे कि राष्ट्रीय यवा संसद योजना और राष्ट्रीय युवा नीति। हालांकि युवा नेताओं के लिए राजनीति में प्रवेश करने के वास्तविक मार्ग बनाने के लिए इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। युवा पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत का उद्देश्य राजनीति में आयु भेदभाव को संबोधित करना और शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। यूएनडीपी, ओएचसीएचआर और अंतरसंसदीय संघ के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में यवाओं का प्रतिनिधित्व बढाने के लिए संयक्त प्रयास हुए हैं। 'नॉट ट यंग ट रन' अभियान राजनीति में युवाओं के सामने आने वाली बाधाओं के बारे में जागरूकता बढाने और सार्वजनिक पद के लिए दौडने की आय कम करने की वकालत करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इन प्रयासों के बावजूद दुनिया भर में निर्वाचित विधायकों में से 2%

सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड चाहिए, पर स्कूल में...



ጆ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

वकीलों को यह समझना चाहिए कि उनकी वेशभूषा उनके पेशेवर आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अदालतें वकीलों के लिए निश्चित स्तर की पेशेवरता की अपेक्षा करती हैं, जिससे अदालत की गरिमा बनी रहे। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि वकीलों के लिए पेशेवरता और गरिमा का पालन आवश्यक है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत चित्रण को दशार्ता है, बल्कि यह अदालत की छवि और उसकी गंभीरता को भी बनाए रखता है अब उच्चतम न्यायालय के आए इस निर्णय की तूलना कोर्ट के पिछले माह दिए गए निर्णय से करते हैं, बात वहां भी ड्रेस कोड की ही थी, किंतु यही माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के निर्णय ने जैसे एक समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहना होगा कि नौ अगस्त को आए एक निर्णय में आज फिर से एक बार उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए विवश कर दिया



कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाई गई थी। इस निर्णय के विरोध में नौ लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी। यहां जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कमार की पीठ का कहना रहा. 'स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है, यह वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते।' पीठ ने मस्लिम छात्रों के लिए 'ड्रेस कोड' को लेकर जन्मे नए विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, छात्राओं को यह चयन करने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था, तो उसने 'तिलक' और 'बिंदी' पर प्रतिबंध क्यों नहीं

भी देख लेते हैं, जो कॉलेज की ओर से जारी किया गया था। वस्तुतः इसमें तीन बिंदुओं में बात रखी गई है- 'एक - छात्रों को परिसर में औपचारिक और सभ्य पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ शर्ट या फुल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं। लड़कियां कोई भी भारतीय या पश्चिमी पोशाक पहन सकती हैं। छात्रों को ऐसा कोई भी परिधान नहीं पहनना चाहिए, जो धर्म या सांस्कृतिक असमानता को दशार्ता हो। नकाब, हिजाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, बैज आदि को ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन रूम में जाकर उतारना होगा और उसके बाद ही वे पूरे कॉलेज परिसर में घूम सकते हैं। जींस, टी-शर्ट, रिवीलिंग ड्रेस और जर्सी की अनुमति नहीं है। दो- अपने व्याख्यान / प्रैक्टिकल के लिए समय से पहले पहुंचें। तीन- 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षा में अनुशासन सफलता की कुंजी है।' यहां गहराई से देखने पर कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक विशेष समुदाय को टार्गेट करके यह आदेश महाविद्यालयों ने निकाला था। हालांकि हम मानकर चलते हैं कि जिस 'बिंदी' का उसके बारे में न्यायालय को भलीभांति पता ही होगा कि सिर्फ हिंदु युवतियां ही 'बिंदी' नहीं

माननेवाली महिलाएं भी लगाती हैं। यानी बिंदी की सार्वजनिक स्वीकृति है। तिलक भी बिंदी की तरह ही एक भाग है, फिर कोर्ट को यह भी पता ही है कि सिख पगड़ी पहनते हैं, उन्हें ये अधिकार सार्वजनिक रूप से हर जगह सामाजिक स्वीकृति के तहत पूरी तरह से मान्य किया गया है। फिर यह स्वीकार्यता इसलिए भी है, क्योंकि भारत की सिख आबादी 20.8 मिलियन है, जो देश की कुल संख्या का केवल 1.72% है। इसका अर्थ है कि एक कक्षा में एक छात्र या अधिकतम दो ही मुश्किल से सिख होंगे, किंतु क्या यह मुसलमानों पर लागू होता है। वह तो देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २९, ३०, ३५०ए तथा 350बी में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। यह विडंबनापूर्ण स्थिति है कि कहीं पर कोई समुदाय जो 96, 98 प्रतिशत है वह अल्पसंख्यक है और वहीं, किसी राज्य में 2 प्रतिशत आबादी वाले लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। संयक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, 'ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।' किंतु, क्या यह परिभाषा भारत में रह रहे मुसलमानों पर लागू होती है। अल्पसंख्यक की अब तक की परिभाषाएं उठाकर देखें। इनमें साफ है कि दो प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत से कम कुल जनसंख्या का अल्पसंख्यक समुदाय कहलाएगा, पर भारत में

पंथों, रिलीजन, मजहब को

लगातीं, उसे तो अन्य तमाम मत. हैं कि 20 करोड़ से अधिक हैं; जो स्वभाविक तौर पर कुल जनसंख्या का 14 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक हो जाता है। दूसरी ओर राज्यीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जाए तो हिंदू, जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहसंख्यक समदाय है. पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है। लक्षद्वीप में 96.20% और जम्मू-कश्मीर में 68.30% मुसलमान हैं, जबिक असम (34.20%). पश्चिम बंगाल (27.5%), केरल (26.60%), उत्तर प्रदेश और (19.30%) (18%) में भी इनकी अच्छी-खासी जनसंख्या है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और वे इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर वे समुदाय, जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त न होने के कारण लाभ से वंचित हैं। विडंबना देखिए, लक्षद्वीप में मात्र दो प्रतिशत हिंदू हैं, लेकिन वे वहां अल्पसंख्यक न होकर बहसंख्यक हैं और 96% प्रतिशत आबादी वाले मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। ईसाई मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में बहसंख्यक हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मे भी इनकी संख्या अच्छी है, इसके बावजूद ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। यह गैर-बराबरी है। इसे एड्रेस किए जाने की जरूरत है, किंतु हर उस मुद्दे में जिसमें न्यायालय को लगता है हस्तक्षेप करना चाहिए, वह करता है, पर यहां इस मुद्दे पर वह अभी तक चुप नजर आता है। यहां माननीय न्यायालय को भी समझना होगा कि उनका दिया गया निर्णय

भीड़-भाड़ को न्योता देते टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें

🯲 रत का टोल रोड 💶 नेटवर्क वर्ष 2023 में 45428 किलोमीटर तक विस्तारित हो गया, जो वर्ष 2019 के 25996 किलोमीटर से 75% विस्तारित है। इस विस्तार के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि हालिया डेटा टोल संग्रह में विलंब को दशार्ता है, जो यातायात भीड़ में योगदान देता है। सड़क यात्रा दक्षता और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए इन चनौतियों का समाधान आवश्यक है, जिसके लिए वर्तमान उपायों के विश्लेषण और अतिरिक्त समाधानों की आवश्यकता है। आज भारत की टोल प्रणाली के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां भीड़-भाड़ और विलंब हैं। फास्टैग सिस्टम शुरू होने के बावजद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें और देरी बड़ी समस्या बनी हुई हैं। तकनीकी गड़बड़ियां और कुछ क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान विधियों का कम इस्तेमाल इस समस्या को और बढ़ा देता है। उदाहरण के

लिए टोल प्लाजा में निरंतर लगने परिचालन लागत में टोल प्लाजा के संचालन और रख-रखाव की लागत, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, बुनियादी ढांचे का रख-रखाव और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, वित्तीय बोझ को बढ़ाती है, जिससे प्रणाली की समग्र दक्षता कम हो जाती है। टोल डेटा में विसंगतियों (जैसे डेटा में हेर-फेर और रिपोर्ट किए गए और वास्तविक टैफिक के बीच भारी अंतर) का खुलासा किया गया है, जैसे कि पुणे एक्सप्रेस-वे पर। टोल दरों में असमानता, अलग-अलग क्षेत्रों और राजमार्गों के हिस्सों में टोल दरों में भिन्नता और वाहन के प्रकारों के आधार पर असंगत मल्य निर्धारण, यात्रियों के बीच भ्रम और असंतोष उत्पन्न करते हैं। टोल मुल्य निर्धारण के लिए पारदर्शिता और स्पष्ट तर्क की कमी जनता के असंतोष को बढ़ाती है। बुनियादी ढांचे के एकीकरण का अभाव होने से कई नेटवर्क या शहरी परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकृत नहीं हैं, जिसके कारण अकुशलताएं उत्पन्न होती हैं। भारत की टोल प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें फास्टैग कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देती हैं और स्वचालित टोल शुल्क कटौती के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर-के टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करती हैं और अब यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। एक राष्ट्र, एक फास्टैग पहल ने देशभर में टोल संग्रह को मानकीकृत किया, जिससे राजमार्ग संचालक या राज्य की परवाह किए बिना सभी टोल प्लाजाओं पर फास्टैग की अंतर-संचालन क्षमता सुनिश्चित हुई, जिससे यात्रियों को एक सहज अनुभव मिला और टोल शुल्क पर भ्रम कम हुआ। सरकार टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ जैसी समस्याओं को दुर करने और दुरी आधारित टोल संग्रह के लिए वाहन ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली का परीक्षण कर रही है, जिससे भौतिक टोल बुथों की आवश्यकता कम हो जाएगी। सरकार ने यातायात की निगरानी और टोल चोरी को रोकने के लिए टोल प्लाजा पर सीसीटीवी सिस्टम लगाए हैं। फास्टैग और नकद भुगतान दोनों को स्वीकार करने वाली हाइब्रिड लेन भी सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फास्टैग का उपयोग कम है। निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए टोल रोड विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पेश किए गए हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को बढ़ाना, सेवा वितरण में सुधार करना और टोल प्लाजाओं का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना है। भारत की टोल प्रणाली को और बेहतर

बनाने वाले उपाय करने की सख्त जरूरत है। जीपीएस आधारित टोल संग्रह, जो यात्रा की गई दुरी के आधार पर शुल्क लेता है, उसे अपनाने में तेजी लाने से भौतिक टोल प्लाजा को समाप्त किया जा सकता है, जिससे भीड़-भाड़ और राजस्व लीकेज को कम किया जा सकता है तथा एक अधिक कुशल, पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है। बेहतर डेटा एकीकरण और विश्लेषण से टोल प्लाजा पर डेटा विश्लेषण और रियल टाइम निगरानी का लाभ उठाकर भीड़भाड़ का पूर्वार्नुमान लगाया जा सकता है, टोल चोरी का पता लगाया जा सकता है और यातायात प्रवाह को अनुकूलित किया जा सकता है, जबकि व्यापक यातायात प्रबंधन प्रणालियों के साथ टोल डेटा को एकीकृत करने से सड़क अवसंरचना प्रबंधन में सुधार होता है। एक गतिशील मुल्य निर्धारण मॉडल जो यातायात की मात्रा और दिन के समय के

व्यस्ततम घंटों में भीड़भाड़ को प्रबंधित करने, अधिक कुशल सड़क उपयोग को प्रोत्साहित करने और अड़चनों को कम करने में मदद कर सकता है। सरकार स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली के साथ निगरानी बढाकर और कठोर दंड लगाकर, अनुपालन में सुधार करके तथा राजस्व संग्रह को बढ़ाकर टोल चोरी पर अंकश लगा सकती है। स्थानीय यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों का विकास और टोल मुक्त सड़कों का विस्तार करने से टोल के प्रति जनता का विरोध कम हो सकता है, जबिक पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के लिए कम दरों की पेशकश से सतत परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकारी पहलों ने कार्यकुशलता के मामले में सुधार किया है, लेकिन भीड़-भाड़ और चोरी जैसे मुद्दों के लिए अधिक सशक्त समाधान की

Social Media Corner

सच के हक में.

क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा? भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर हो कर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं।

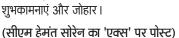


भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देशभर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीन कर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर हो कर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछडे इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में, अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे।

(राहुल गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

से भी कम युवा हैं।

इटखोरी की पावन धरती चतरा में चतरा और कोडरमा जिले के लाभुकों के बीच आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार हेतु आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ। सभी को अनेक-अनेक बधाई,





विकास में रुकावट आई।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने दूसरे

कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय

का गठन करने और अमित शाह

को इसकी कमान सौंपने के बाद

निया भर में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष- 2025 के स्वागत की तैयाग्रियां जेप

ऐसे समय में हो रहा है, जब

शोर से चल रही हैं। यह

लगी। गुजरात में सहकारिता आंदोलन को नया आकार देने वाले सुधारों के लिए विख्यात सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रीय सहकारिता परिदृश्य में बड़े पैमाने पर सुधार किए, जिससे दुनिया इस क्षेत्र की ओर उम्मीद से देखने लगी। सहकारिता की क्षमता को अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के साथ हुए बजट परामर्श में भारतीय सहकारी (एनसीयुआई) ने प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाने की सिफारिश की। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली वजहों से अच्छी तरह परिचित हैं। इन बाधाओं में पीएसीएस विविधीकरण की कमी थी, जिसने उन्हें लगभग अव्यवहार्य बना दिया।। शाह ने पीएसीएस के लिए

सहकारिता क्षेत्र में बदलाव दिखने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, वह उनके बायलॉज यानी उप-नियमों में बदलाव लाना था। पीएसीएस की समस्याओं से छुटकारे के लिए मॉडल बायलॉज लाकर उन्हें बहुद्देश्यीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ कर विविधता लाने में मदद मिली है। अब वे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य पैन कार्ड आई आर सीटीसी/बस/ह वाई टिकट आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 35000 से अधिक पीएससीएस ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही अब उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके), जल समितियों, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों,

किसान उत्पादक संगठनों (एपपीओ) आदि के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है। पीएसीएस अब गांवों में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेएके) के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पीएसीएस की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का अगला महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना था, जो दशकों से कुप्रबंधन से ग्रस्त था। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 63000 पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक 23 हजार से अधिक पीएसीएस को एंटरप्राइज रिसोर्स (ईआरपी) सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

उल्लंघन रोके

जनवरी 2023 से अपने चौथे नोटिस में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यटी) पर दोबारा बातचीत की मांग तेज कर दी है। उसने पाकिस्तान के वार्ता की मेज पर आने के लिए राजी होने तक स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। पिछले साल भारत की मांग के बाद उस पूरी प्रक्रिया में गतिरोध आ गया, जिसे कभी जल बंटवारा समझौते के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श उदाहरण माना जाता था। नई सहस्राब्दी में भी इस संधि के सिद्धांत मजबूती से कायम थे और भारत स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दो बड़े विवाद जीतने में सफल हुआ, जिसमें 2007 में बगलिहार बांध परियोजना और एक अन्य विवाद शामिल है, जो 2013 में पाकिस्तान की नीलम परियोजना में भारत के दखलअंदाजी करने के आरोप को लेकर पैदा हुआ था। किशनगंगा और रतले परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, यह मसला 2016 में पाकिस्तान द्वारा विवादों को तूल देने के बाद से काफी बड़ा बन गया है। पाकिस्तान ने इन पर तटस्थ विशेषज्ञ अवलोकन और स्थायी मध्यस्थता अदालत (पीसीए) की मांग की है। एक कमजोर लम्हे में, जिसके लिए उसे पछताना पड़ सकता है, विश्व बैंक (जो आईडब्ल्यूटी का सह-हस्ताक्षरी और गारंटर है), ने विवाद निपटारे की दो समांतर प्रक्रियाएं एक साथ चलाने का निर्णय लिया। मामले को बदतर बनाते हुए, पाकिस्तान ने तटस्थ विशेषज्ञ की कार्यवाहियों से मुंह फेर लिया है, जबकि भारत ने हेग में पीसीए की सुनवाइयों का बहिष्कार किया है। संधि पर फिर से बातचीत करने के भारत के नोटिस के प्रति पाकिस्तान उदासीन है और मोदी सरकार द्वारा पीआईसी की सभी बैठकें रोक देने के फैसले से यह प्रक्रिया खतरे में पड गई है। बीते दशकों के उलट, जब आईडब्ल्यूटी को पक्षपाती राजनीति के लिए निषिद्ध माना जाता था, दोनों पक्षों के नेता अब उग्र बयानबाजी से परहेज नहीं कर रहे हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail: thephotonnewsjharkhand@gmail.com

सहकारी क्षेत्र में नई जान फूंकेंगे पीएसीएस

Playing for country, for money

Rio de Janeiro 2016. The Olympics mixed doubles semifinal is on, and an Indian tennis legend is getting a bit anxious, for there looms the real possibility that Sania Mirza and Rohan Bopanna would beat Venus Williams and Rajeev Ram.

Sania and Bopanna won the first set 6-2, and we fans, sports writers, coaches, Indian sportspersons — were hoping for an encore in the second... All except the anxious legend. He didn't want Sania and Bopanna to win a silver or any medal! — because he had not been picked to partner Sania in the Olympics. Sania-Bopanna were, also, foes to him, for they were members of the camp of his former male doubles partner. Thus, he was willing hard, with all his heart, for Sania-Bopanna to fail, to lose in the semifinals, to not win a medal — the Indian medal count be damned. In the event, Sania and Bopanna lost the second set 2-6 and the third 3-10 to Venus-Ram; they still had the opportunity of winning a medal, a bronze, but they lost the third-place playoff 1-6, 5-7 to Radek Stepanek and Lucie Hradecka. It was a heartbreaking loss for Sania-Bopanna, for the Indian media pack, for the Indian fans — but not so for the aforementioned legend.

the anxiousness of this great player at the possibility of a medal for Sania-Bopanna, and then the glee at them missing it — came to one's mind when controversy broke out over India No. 1 Sumit Nagal demanding \$50,000 from the All India Tennis Association to play for India in the Davis Cup tie against Sweden. India, missing top singles stars Nagal, Sasikumar Mukund and Yuki Bhambri, got a 0-4 hammering from Sweden.

Sportspersons are human, not exemplars of morality, rectitude, patriotism. They're just like us — and possibly we're a bit better, because we're never exposed to the temptations that some sportspersons, especially cricketers, face every day of their lives. And if they do give in to temptation, those watching from the sidelines start booing. Sportspersons turn cynics when quite young, for their experience, of fellow players and coaches, tells them that the sports administrator is venal and undependable — often a politician or bureaucrat or businessman who joins up for clout in his city, then country, then the world. Once they have the vote in, say, the global governing body of a sport, or in the Olympics, such men are like kings — feted and lionised at the biggest sports events in the world. Power can be difficult to digest for the petty — they turn autocrats, treating athletes like menials.

Some of these men turn up at, say, the tennis event at the Olympics, sozzled silly, courtesy complimentary alcoholic beverages. We in the media have seen them countless times, as have athletes. Sportspersons have utter contempt for such freeloaders. Somdev Devvarman, the former India No. 1 who had a highest global ranking of No. 61, said in 2017 about certain AITA officebearers who had missed the fourth and fifth sets of his Davis Cup match in 2014: "They were getting late for their single malt party down at the club as they thought my match was done and I had no chance of coming back. This information certainly didn't come as a surprise to me. I expect them to be unpolished. I also got a solid whiff of their single malt Scotch as they poured over me with congratulations after the match."Nagal, facing criticism for asking for money to play for India, clarified: "It is standard practice in professional sports for athletes to be compensated for their participation in events, even when representing their country.

Nagal also said he was undergoing rehab after an injury, and had informed "AITA well in advance about my inability to participate" in the Davis Cup.It must be stated that playing tennis as a pro — with the need for a team of coach, physio, trainer, doctor, etc — is a very expensive proposition, and players do need to focus on their bread and butter, the ATP tournaments.AITA officials did not reveal that the association does get money from the International Tennis Federation with which to compensate Nagal — that players do get paid for playing in the Davis Cup

Don't let the State trample over the law of the land

While courts can be expected to perform their assigned tasks, it would be unfair to impose a disproportionate burden on the judiciary.

THE Supreme Court's interim order of September 17, staying the demolition of properties of persons accused in criminal cases, is premised on the unexceptionable principle of constitutional governance, that the exercise of State power is accountable to the discipline of the Constitution. It is a reminder to the executive authorities that in a State governed by the rule of law, mere lip service to procedural niceties is not a sufficient assurance of substantive compliance with the mandatory requirements of legal due process. The court's order, rooted in 'the ethos of the Constitution', echoes the outraged conscience of the nation against the State's exercise of brute force in meting out retributive justice. That the order was resisted in court by the government in a matter seen as a frontal assault on constitutional conscience and an indelible scar on the soul of the nation speaks for itself. The court's intervention in a petition filed by the Jamiat Ulama-i-Hind in the wake of widely reported demolitions across the country was sought on the touchstone of Article 21 of the Constitution that guarantees to all individuals the right to life with dignity, which includes the right to shelter, privacy and reputation. Though belated, the court's order interdicts what is now infamously known as 'bulldozer justice', a punitive mode wholly incompatible with the first principles of constitutional justice. In a purposive judicial intervention, the court proposed a set of guidelines on a 'pan-India basis' to prevent unlawful demolitions anywhere in the country and has thus exercised its plenary jurisdiction to fill a legal vacuum. In a perfect harmonising of equities, it has ruled that the injunction regarding demolitions would not apply in cases of encroachment of public spaces such as "road, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies and also to cases where there is an order for demolition made by the court..."It is worrisome that the apex court's intervention came after several residential and commercial premises were unlawfully razed in what is prima facie a legally indefensible action across several states, such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra and Delhi. Even as attempts to justify 'bulldozer justice' persist, the unlawful use of brutal force by executive authorities to deprive citizens of their homes and places of work has shamed the nation. We are compelled to ask ourselves if there is "fair play for poor as well as for rich, for private persons as well as government officials" and whether "the right of the individual, subject to his duties to the State, be maintained, asserted and exalted" (from Winston Churchill's 1938 speech, expounding the necessary conditions of democracy). Clearly, as long as the sanctity of our homes is not secure against unjust State intrusion, the cherished ideal of Gandhi's Swaraj and a vision of a libertarian democracy in which, "...the poorest man may



in his cottage bid defiance to all the force of the crown..." will remain a distant dream. Discriminatory, disproportionate, arbitrary and violative of the rule of law, 'bulldozer justice' is an anathema to any civilised society, especially in a country whose political and social consciousness has been shaped in the crucible of a long and arduous struggle for freedom gainst the oppressive colonial rule.

In the cause that is yet to be argued, the court is expected to respond to the constitutional command in an unapologetic assertion of its remit. Summoned to defend fundamental freedoms, it must revalidate its role as the nation's impartial judicial arbiter by scripting a credible remedy that will minimise, if not eliminate, the excesses of the State against its citizens. But the issue at hand raises larger questions: Must citizens be compelled to approach the highest court for relief against recurring high-handedness of the executive branch? Can a constitutional State sanction retribution through processes unknown to law and extend the consequences to the innocent family members of the accused, including women, children and the elderly, depriving them of a roof over their heads and the means of subsistence? Implicit in the interrogatory is a perceived perversion of constitutional governance at different levels that compels an urgent review of the nation's governing processes to ensure that administrative justice meets the test of fairness. While courts can be expected to perform their assigned tasks, it would be unfair to impose a disproportionate burden on the judiciary, considering the institutional limitations. The defence of democracy and the rule of law is, after all, the collective burden of the three wings of the Indian State and, in the ultimate analysis, of the people as a whole, who must write their own story through peaceful democratic assertion against unjust actions of the State. As a repository of the people's power, the government is expected to exercise its authority in demonstrable compliance with the established legal procedures so that justice is not only done but is also seen to be done. We must confront a broader question: is the smallness of our politics conducive to the establishment of a just society? Indeed, it is necessary to state the obvious and ask difficult questions, lest we forget who we are. No apologies are owed for condemning the unacceptable, particularly, the inhuman acts that have wounded national sensitivities and have left behind an unhealable pain in an unending 'daze of grief'. By a robust refusal to countenance injustice and abuse of power, Justices BR Gavai and KV Viswanathan have once again vindicated the oath of their high office. In their path-breaking judgments on bail and 'bulldozer justice', the judges have validated the view of distinguished historian Arnold Toynbee that the history of the human civilisation is the history of how civilisations respond to challenges that shape the world. The tragedy of 'bulldozer justice' and the court's action will doubtless define the future course of India's democracy.

Lankan mandate

Onus on Dissanayake to bolster economy

TWO years after an economic meltdown sparked an uprising in Sri Lanka, Marxist-leaning Anura Kumara Dissanayake has bested Sajith Premadasa in the presidential election. Incumbent President and six-time Prime Minister Ranil Wickremesinghe finished a distant third, underlining the voters' resolve to herald a new beginning in the beleaguered island nation. Dissanayake, the candidate of the National People's Power (NPP) alliance, rode to victory on the back of his anti-corruption and pro-poor agenda. His promise of slashing taxes clicked with people who are reeling under poverty or finding it hard to keep pace with the high cost of living.

Involved in two armed uprisings against the Lankan government (1971 and 1987-89), Dissanayake's Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) has been active in mainstream politics in recent decades. It remains to be seen if the NPP will give him and his party the freedom to do something revolutionary on the economic front. A deal with the International Monetary Fund has helped Sri



Lanka's economy make a tentative recovery, with inflation falling to 0.5 per cent from an alarming high of

70 per cent. The major challenges for Dissanayake are to enable the country to repay its debt, regain investors' confidence and pull one-fourth of its population out of poverty. He can't afford to let down the masses, whose anger and discontent had fuelled the 2022 protests that led to the ignominious ouster of then President Gotabaya Rajapaksa. Those nightmarish scenes of food and fuel shortages are fresh in the people's minds.

Playing its cards well, the Modi government had hosted Dissanayake in February, notwithstanding the anti-India rhetoric the JVP was once infamous for. Going by Delhi's diplomatic success in making pro-China Maldives President Muizzu see reason, India will hope to sway Dissanayake in case he starts cosying up to Beijing. A balancing act by the

new President will stand his country in good stead geopolitically as well as economically.

'One nation, one poll' faces trust deficit

Altering an established democratic system and the Constitution raises serious concerns

DESPITE opposition from political parties and civil society, the Union Government, on September 18, decided to move forward with simultaneous elections, accepting recommendations from a high-level committee led by former President Ram Nath Kovind. The committee proposed that Lok Sabha and Assembly elections be held together, with municipal and panchayat elections following within the next 100 days. To implement this plan, the government will need to secure constitutional amendments.

will need to secure constitutional amendments in both Parliament and the Assemblies. The issue of simultaneous elections has been raging for decades. In 2013, before becoming the Prime Minister, Narendra Modi had emphasised the need for simultaneous elections, citing high costs and disruptions to development activities. Since then, various committees have examined the issue but failed to reach a viable solution. It was in this context that the Kovind-led committee was formed, with a clear mandate to propose concrete methods for holding simultaneous elections rather than debating the

merits of the proposal.

The committee delivered a comprehensive report within the mandated time frame. Established on September 2, 2023, it worked for 191 days and submitted an 18,626-page report on March 14, 2024. Its members included distinguished individuals from various fields. It sought inputs from political parties and legal experts, including former chief justices, former chief election commissioners and state election commissioners. Suggestions from the public were welcomed, with organisations like the Bar Council of India, the Confederation of Indian Industry and the Federation of Indian Chambers of

present their views. The report indicated that 21,558 responses were received, with 80 per cent supporting simultaneous elections. But critics have pointed out that suggestions were invited only in Hindi and English. Therefore, the response is not reflective of all regions of India. Inputs came from 47 political parties, of which 32 (all members of the NDA) favoured the proposal and 15 opposed it, labelling it

Commerce and Industry given opportunities to



anti-democratic and anti-federal. Opposing parties raised concerns that the move could marginalise regional parties, promote national party dominance and lead to a presidential-style government. Based on these contributions and thorough research, the committee conducted an in-depth analysis.

Supporters of simultaneous elections argue that separate polls waste resources and lead to policy paralysis. While a majority of the experts agree that constitutional amendments are necessary, they contend that these changes would not be anti-democratic or anti-federal, nor would they undermine

the Constitution's basic structure or lead to a presidential form of government. A significant strength of the report is its comprehensiveness, consisting of 21 volumes of annexures, as it faithfully reproduces all past and present opinions, making it a valuable document. The committee unanimously recommended that simultaneous elections be implemented nationwide. It proposed necessary

amendments to the Constitution and laws, including a new Article, 82A, stating that "notwithstanding anything contained in Articles 83 and 172, all the legislative assemblies constituted in any general election held after the appointed date shall come to an end on the expiry of the full term of the House of the people." It clarified that "simultaneous elections" refers to elections for the Lok Sabha and all Vidhan Sabhas, excluding panchayat elections, which are proposed to be held "within 100 days". However, this does not amount to simultaneous

However, this does not amount to simultaneous elections. In fact, the proposed remedy may be worse than the current situation. First, it leaves out over three million elected representatives compared to the 5,000 included. Moreover, an election held three months later is not a simultaneous election but constitutes are absolutely now one

election held three months later is not a simultaneous election but constitutes an absolutely new one, necessitating all logistical preparations again — setting up polling stations, selecting and training polling parties and redeploying security. All this has to be done within three months, when the 15-million staff would have barely recovered from what is officially described as the largest management exercise in the world. Importantly, voters would have to return to the polls and millions of them will not be able to do so as they are poor daily-wage workers, losing their important constitutional right. The report

also states that "where any state legislative assembly is dissolved on account of a no-confidence motion, a hung House, or any other event, fresh elections will be held for such a new House with the tenure ending with that of the House of the people." This provision does not eliminate the possibility of midterm polls. Candidates could end up spending crores on an election for a truncated term — potentially as short as one to two years. This certainly does not constitute simultaneous elections. The committee has commendably emphasised the need for a single electoral roll by proposing an amendment to Article 325, recognising that the voters for all three tiers of elections are the same. This essentially shifts the responsibility for local bodies' electoral rolls to the Election Commission of India (ECI) "in consultation with State Election Commissioners", a task that is far from simple. It has also acknowledged the ECI's "detailed requirements for equipment such as EVMs, VVPATs, polling personnel, security forces, and election materials", along with expenditure estimates. Although the specific costs are not mentioned, it is clear that we will require at least three times the current number of EVMs and VVPATs, which would entail humongous expenses on nearly 40 lakh EVMs and VVPATs each, that should have been explicitly outlined, especially since cost reduction is one of the main reasons for this proposal. With such significant compromises, the moral authority of the simultaneous poll proposal has been undermined. Altering an established democratic system and the Constitution raises serious concerns. If the proposal were sincere, why have all elections been extended over the past decade? Why have the Himachal and Gujarat elections.

Western Carriers makes weak D-Street debut, lists at 1% discount

NEW DELHI. Western Carriers had a lackluster debut on Dalal Street, listing at a slight discount on Tuesday. The company's shares opened at Rs 170 on the BSE, 1.16% below its issue price of Rs 172. On the NSE, the stock listed at Rs 171, down by Rs 1 or 0.6%. Despite the weak listing, the IPO received strong investor interest, being oversubscribed nearly 31 times, primarily driven by noninstitutional investors. The proceeds from the IPO will be used to repay debt, finance capital expenditures for the purchase of commercial vehicles, containers, and reach stackers, with the remaining funds allocated for general corporate purposes. Western Carriers operates a vast logistics network across India, with over 50 branch offices and four zonal offices in

The company also manages 16 warehouses across 12 states and operates at more than 55 major public rake handling points, providing first-mile and last-mile connectivity for clients in diverse industries such as metals, FMCG,



pharmaceuticals, chemicals, and oil &

As of March 31, 2024, Western Carriers had 1,647 clients, including notable names like Tata Steel, Hindalco Industries, HUL, and DHL. Its consolidated revenue from operations rose 4% in FY24 to Rs 1,686 crore, while profit after tax increased by 12% to Rs 80.3 crore. The company maintains a high customer retention rate, with 80% of its FY24 revenues coming from clients who have been with the company for over three years. The retention rate for its top 10 customers was

JM Financial and Kotak Mahindra Capital Company served as the lead managers for

Retail Investors Lost Rs 1.8 Lakh Cr In FY22-FY24 In Equity Futures **And Options: Sebi Study**

Mumbai. The aggregate losses of individual traders in the equity futures and options (F&O) segment exceeded Rs 1.8 lakh crore over the three-year period between FY22 and FY24, a new study by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) showed on Monday. Over nine out of 10 individual traders in the equity futures and options segment continue to incur significant losses, revealed the study, adding that despite consecutive years of losses, more than 75 per cent of loss-making traders continued trading in F&O.The proportion of young traders (below 30 years) in the F&O segment rose from 31 per cent in FY23 to 43 per cent in FY24. Moreover, individuals from beyond top 30 (B30) cities made up over 72 per cent of the total F&O trader base, a higher proportion compared to mutual fund investors, 62 per cent of whom are from B30 cities. About 93 per cent of over 1 crore individual F&O traders incurred



average losses of around Rs 2 lakh per trader (inclusive of transaction costs) during the study period. Top 3.5 per cent of loss-makers, approximately 4 lakh traders, faced an average loss of Rs 28 lakh per person over the same period, inclusive of transaction costs.Only 1 per cent of individual traders managed to earn profits exceeding Rs 1 lakh, after adjusting for transaction costs, the findings showed. The SEBI study found that in contrast to individual traders, proprietary traders and Foreign Portfolio Investors (FPIs) as a class booked gross trading profits of Rs 33,000 crore and Rs 28,000 crore, respectively in FY24 (before accounting for transaction costs). Against this, Individuals and others incurred a loss of over Rs 61,000 crore in FY24 (before accounting for transaction costs). Most of the profits were generated by larger entities that used trading algorithms, with 97 per cent of FPI profits and 96 per cent of proprietary trader profits coming from algorithmic trading, said the study.On an average, individual traders spent Rs 26,000 per person on F&O transaction costs in FY24.Over the threeyear period from FY22 to FY24, individuals collectively spent about Rs 50,000 crore on transaction costs.

Festive sale: Amazon hikes content creator commission

BENGALURU. Ahead of the festive sale, ecommerce company Amazon has announced an increase in its standard commission income rates for key categories within its network of more than 50,000 influencers engaged with it.

The platform said the revised commission structure offers influencers a substantial increase ranging from 1.5x to 2x across a wide range of product categories, including fashion, beauty & personal care appliances for active creators working with Amazon."By significantly increasing commission rates across key categories and offering additional resources via programs like Creator University and Creator Connect, we're providing creators with tools and incentives they need to thrive during emerging markets, Amazon.

In addition to fee changes, as part of Amazon Live program, hundreds of creators will run over a 1,500 live streams across categories including mobiles, home appliances, home



décor, fashion and beauty among many others festive season and beyond," said Zahid Khan, Meanwhile, Flipkart is gearing up for the festive season by offering a diverse mix of petrol and electric two-wheelers from leading brands including Hero, TVS and Bajaj, among others. Demand for two-wheelers on Flipkart has soared by 6x in August 2024 over last year.

Production at Tamil Nadu plant returning to normalcy: Samsung

NEW DELHI. Samsung on Monday said production at its Sriperumbudur plant in Production at Tamil Nadu plant returning Tamil Nadu has returned to normal capacity despite the ongoing employee strike. Employees at the plant, which manufactures consumer goods like televisions, refrigerators, and washing machines, have been protesting for better pay and reduced working hours for the past 15 days. Initially, production was hit by nearly 50%, but the company has since hired contractual employees, and production is now nearly back to normal. "The strike at Chennai factory, now in its 15th day, hit the production of consumer goods such as televisions, refrigerators, and washing machines initially. However, the impact of the strike is minimal now, and the company expects production to be near normal

starting this week," said Samsung. to normalcy: Samsung

Samsung workers in Sriperumbudur continue strike, call for recognition of union and self-respect

The plant is a crucial production unit, accounting for one-third of its annual revenue in India, about USD 12 billion. The strike, began on September 9, was driven by workers' demands for higher wages, a raise from Rs 25,000 to Rs 36,000 over the next three years, and official recognition of their union, backed by the Centre of Indian Trade Union (CITU). Samsung has taken legal action, approaching a district court to obtain a temporary injunction against the union to prevent protests near the

Vodafone Idea shares fall 2% as ICICI Securities cuts target price

ICICI Securities has reduced Vodafone Idea's EV/EBITDA multiple to 13 times FY27 from 14 times and lowered its target price to Rs 11 from Rs 15.

New Delhi. Vodafone Idea shares declined over 2% after ICICI Securities slashed its target price, citing concerns over the company's financial outlook. At 11:36 am, shares of the telecom operator were down 2.03% at Rs 10.60 on the Bombay Stock Exchange (BSE). Following an analyst call with the management, ICICI Securities noted that Vodafone Idea remains hopeful of resolving an "arithmetical error" in the calculation of its Adjusted Gross Revenue (AGR) dues. The telecom operator is currently engaging with the government on the matter, despite the Supreme Court's rejection of its curative petition regarding these dues. According to ICICI Securities,



Vodafone Idea believes its case has strong merit, and discussions with the government have been encouraging. The company is factoring in the conversion of Rs 29,000 crore of government debt into equity at the end of the moratorium period under the recent telecom reform package.

While Vodafone Idea has not included AGR relief in its business recovery plan, ICICI Securities moved its estimate of AGR relief worth Rs 35,000 crore from FY25 to FY26. This shift, along with the delayed capex acceleration, resulted in revised net profit projections for FY25-27E, although its EBITDA estimate for the same period remains unchanged. Given the rising uncertainty surrounding the AGR resolution, ICICI Securities reduced

13 times FY27 from 14 times and lowered its target price to Rs 11 from Rs 15. The brokerage maintained a 'Hold' rating on the stock. Meanwhile, Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) has a target price of Rs 12 and a 'Neutral' rating.

ICICI Securities also noted that Vodafone Idea is close to finalising Rs 25,000 crore in debt funding, with an additional Rs 10,000 crore for non-fund facilities, which should bolster its capex efforts.

The telecom firm has signed agreements with major equipment suppliers for Rs 30,000 crore worth of radios, set to be delivered over the next three years. Capex is expected to begin in November 2024, alongside a potential tariff hike of 15-20% over the next 15 months. Meanwhile, Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) highlighted that despite the company's high operating leverage, the significant cash required to service its debt limits the upside potential The latest grey market premium (GMP) for the for equity holders. The conversion of unpaid installments into equity postmoratorium could start by FY26/FY27, further affecting the company's financial

Manaba Finance IPO Day 2: Check latest subscription, expected listing gains

New Delhi. The initial public offering (IPO) of Manba Finance has seen strong interest from investors as it was fully subscribed on the day it opened for bidding. Manba Finance Limited, founded in 1998, offers a variety of financial services, including loans for new two-wheelers (2Ws), three-wheelers (3Ws), electric two-wheelers (EV2Ws), electric three-wheelers (EV3Ws), used cars, along with small business and personal loans. The IPO of Manba Finnace is a fresh issue of 1.26 crore shares and closes for subscription on September 25, 2024.Manba Finance IPO was subscribed 39.56 times overall by 11:39 AM on September 24, 2024. The retail category saw a subscription of 44.10 times, while the QIB category was subscribed 3.05 times, and the NII category reached 77.65 times. The price range for Manba Finance's IPO has been set between Rs 114 and Rs 120 per share. Investors are required to apply for a minimum of 125 shares. For retail investors, the minimum investment amount is Rs 15,000.Latest grey market premium (GMP) for Manba Financen IPO



Manba Finance IPO stands at Rs 64, as of 11:01 AM on September 24, 2024 With a price band set at Rs 120, the estimated listing price for Manba Finance shares is expected to be around Rs 184 (calculated by adding the cap price to the current GMP). This suggests a potential gain per share of 53.33%. While the projected 53.33% gain looks attractive for investors seeking quick returns, it's important to remember that grey market premiums can

due to market conditions on the day of listing. Should you subscribe?

An IPO report from Anan Rathi said that Manba Finance Bank Ltd has established relationships with more than 1100 dealers with the ability to expand to new underpenetrated geographies (currently present in 66 locations spread across six states in western, central and north India) and a Technology drive and scalable operating model with quick Turn Around Time (TAT) for loan processing (5.30 days as of March 31,

fluctuate, and actual listing prices may vary

Telecom sector is robust, should have four service providers, says Scindia

The minister noted that very few countries have four major players in their telecom markets, with India being one of them.

NEW DELHI. Communications Minister Jyotiraditya Scindia on Monday advocated for at least four telecom operators in the country, emphasizing that the telecom sector is very robust. The minister noted that very few countries have four major players in their telecom markets, with India being one of them. Following the Supreme Court's rejection of a curative petition filed by telecom service providers seeking a re-computation of their Adjusted Gross Revenue (AGR) dues, Scindia mentioned that Supreme Court orders need to be



The minister stated that the government is currently examining the implications and repercussions of the court's order and acknowledged that it must be executed.

"So, the Supreme Court's judgment has just come out. Whatever its order may be, it must be executed. We are still in the process of examining it and assessing its potential

repercussions. But let me say this: our telecom sector is extremely robust. It's a sector where we have four players. There are very few countries in the world that can boast of having four players within their telecom sector. India is one of those," said Scindia. Scindia highlighted India's fastest 5G rollout, with 4.5 lakh base tower stations installed and 97% of cities covered with 5G. The telecom sector's robustness enabled this achievement, with Rs 4.26 lakh crore invested in capex over two years.

Regarding 4G coverage in uncovered villages, a total of 7,101 4G mobile towers have been commissioned by the telecom service providers including Reliance Jio, Bharti Airtel, and BSNL, under various Digital Bharat Nidhi-funded 4G schemes, including the 4G saturation scheme. Out of these, 2,618 towers have been made operational since June 2024.

GoM to discuss rate rationalisation on September 25

NEW DELHI. The Group of Ministers responsible for Goods and Services Tax (GST) rate rationalisation is set to convene on September 25 in Goa to deliberate on potential adjustments to tax slabs and rates.

The six-member Group of Ministers (GoM), led by Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary, last convened on August 22.

They submitted a status report to the GST aims to finalise the process of GST rate rationalisation by the end of the year, as per sources. According to sources, the panel is likely to deliberate on the possibility of merging 12% and 18% goods and services tax slabs into a single unified rate, though no formal proposal has been put forward yet. Meanwhile, the Centre is also concerned about the revenue generation -- the average In a similar vein, Karnataka Revenue Minister GST rate at about 12% is below the revenueneutral rate of 15.3%.

"The revenue-neutral rate is crucial as it represents the level at which government revenue remains stable following the implementation of GST. The lower-thananticipated average rate has raised concerns about the government's ability to generate adequate revenue, leading the Group of Ministers (GoM) to initiate discussions on possible adjustments to the existing tax rates. However, not all states are in agreement with the idea of altering the goods and services tax structure," a top source told

Council on September 9. The government Notably, both West Bengal and Karnataka have voiced their concerns and are hesitant to support any immediate changes to the tax slabs. Following the August meeting, West Bengal finance minister Chandrima Bhattacharya expressed her opposition to changing the current goods and services tax rates, advocating for the preservation of the existing structure.

> Krishna Byre Gowda remarked that the GST system has largely stabilized over the past few years, warning that any alterations could upset this equilibrium. He also mentioned that the Group of Ministers (GoM) would revisit this topic in their next meeting.



The six-member Group of Ministers (GoM), led by Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary, last convened on August 22.

Karnataka High Court bars using, uploading videos of hearings amid Pak remark row

The court has also ordered social media platforms, including YouTube, Facebook, X to takedown the videos taken, and uploaded from the **High Court's** official livestreaming footage.

High Court on Tuesday prohibited the public from using or uploading videos of court proceedings, the Bar and Bench reported. This development comes after two video clips featuring Karnataka High Court judge Justice V Srishananda, making controversial remarks, went viral. The court has

also ordered social media platforms, including YouTube, Facebook, X to takedown the videos taken, and uploaded from the High Court's official live-streaming footage.Justice Hemant Chandangoudar also directed certain social media users to delete the videos of court proceedings from their social media handles. "Till next date, respondents 6 to 8



[social media platforms] and 9 to 14 [private respondents] are restrained from displaying the videos on their channels. Any video already uploaded in violation of Rules must be deleted," the court's interim order was quoted by the Bar and Bench in its report. The court, while issuing a notice on a petition filed by the Advocates' Association in Bengaluru, addressed concerns over the public use of live-streamed court proceedings, particularly on social media platforms. The video clips featuring Karnataka High Court judge Justice V Srishananda, making controversial remarks, went viral.

Despite the association's request to stop livestreaming, the court made it clear that stopping the broadcasts was not the

answer to the misuse of such videos. Justice Chandangoudar emphasised that while the morale of lawyers could be impacted, judges and lawyers alike must develop resilience."You have to be thickskinned. Even judges have to be thick-skinned. I agree that lawyers' morale can be affected, but the solution is not to stop livestreaming. If any offence is committed, bring it to the judge's notice," he remarked.

petition was filled after two The Advocates' Association of Bengaluru has filed a petition in the Karnataka High Court, seeking measures to prevent the public from editing, morphing, or illegally using live-streamed court proceedings. The plea also asked for a directive to social media platforms like YouTube, Facebook, and X (formerly Twitter) to remove any videos or reels created using footage from the court's live-streams.

This legal move followed widespread criticism of two video clips featuring Justice V Srishananda. In one video, the judge referred to a Muslim-majority neighbourhood in West Bengaluru as "Pakistan." In another, he made a genderinsensitive comment while addressing a woman lawyer. These remarks ignited public outrage,

prompting the Advocates' Association to request that livestreaming be paused until clear guidelines on courtroom conduct are established. The controversy caught the attention of the Supreme Court, which asked the Karnataka High Court Registrar General for a report on the matter. Justice Srishananda later expressed regret for his comments. During the hearing of the Association's petition, Additional Solicitor General Arvind Kamath highlighted that the High Court already has mechanisms in place to address complaints about video misuse. He stated, "If an offence comes to someone's notice, only a complaint has to be made, and action will be taken." Kamath also defended the live-streaming of court proceedings, calling it a "boon" for transparency in the judicial process.

Arrest Warrant Against Actor Siddique In Rape Case, Cops Begin Search

The charges stem from a complaint filed by an actress who alleged that Siddique raped her at a state-owned hotel in Thiruvananthapuram in 2016.

New Delhi: Kerala Police are reportedly gearing up to arrest actor Siddique following the Kerala High Court's decision to deny him anticipatory bail in the Malayalam cinema #MeToo case, sources said. The court rejected Siddique's bail plea in a rape case lodged against him by a former actress. A lookout circular has been issued as police intensify efforts to trace Siddique's whereabouts. The charges stem from a complaint filed by an actress who alleged that Siddique raped her at a state-owned hotel in Thiruvananthapuram in 2016. According to sources, the victim had initially refrained from reporting the incident but came forward after the explosive Hema Committee

report was released last month. The report highlighted the systemic abuse and harassment faced by women in the Malayalam film industry, encouraging several former actresses to share their stories of exploitation. The actress, in her complaint, claims that Siddique coerced her into providing sexual favours in exchange for a role in a Tamil movie. When she refused, he allegedly raped her. Siddique, who was recently elected general secretary of the Association of Malayalam Movie Artistes (AMMA), resigned from his post soon after the allegations surfaced, prompting the entire committee, chaired by actor Mohanlal, to step down as well. Siddique has denied the allegations, accusing the complainant of harassing him since 2019 by repeatedly making baseless claims on social media. According to Siddique, the actress had previously accused him of misbehaving with her at a theatre in 2016, but only after the Hema Committee report did she escalate her allegations to rape.

"What Are We Doing To Education System?" Chief Justice On Punjab NRI Quota

New Delhi: The NRI quota system in college admissions was nothing but a fraud, the Supreme Court said today as it dismissed the Punjab government's appeal against a high court order that junked amended rules to avail admission to MBBS courses through this quota. The Punjab government had, in a notification dated August 20, widened the

definition of an NRI candidate and made relatives of Non-Resident Indians (NRI) eligible to seek admission to the MBBS course under this quota. The Punjab and Haryana High Court shot down this notification, observing that this "opens the door for potential misuse".In the Supreme Court today, the Punjab

government's counsel said that Himachal Pradesh and Uttar Pradesh were following a broad definition for NRI quota admissions. "HP, UP, Chandigarh, everyone is following the definition which I am saying... so only I am under (a) narrow definition," he said. Chief Justice of India DY Chandrachud replied, "You are saying the nearest relation of NRI will also be considered. what is this? just a money-spinning tactic by the state."The bench, also comprising Justice JB Pardiwala, backed the high court order. "We must stop this NRI quota business now! This is a complete fraud. This is what we are doing to our education system," the Chief Justice said. "Look at the result. Those who got marks three times high won't get admission," he added. Justice Pardiwala said all the applicants are from India. "They are just

relatives, tai (aunt), taau (uncle), chacha, chachi." The Chief Justice said, "What is a ward? you just have to say I am looking after X." He said the court cannot back something that is "blatantly illegal".

Gujarat school principal kills girl for resisting rape, dumps body; arrested

The principal said that when he tried to rape the girl, she started screaming. He put his hands on her mouth tightly to stop her screaming. However, the girl died, following which he hid her in the back of the car. He took her body and left it inside the school compound in the evening, after the classes were over.

New Delhi. The principal of a primary school in Pipaliya in Gujarat's Dohad district was arrested for allegedly killing a 6-year-old girl of the school

after she resisted his rape attempts. The body of the girl, who studied in Class 1 in the school, was found in the school compound on September 19. The postmortem report of the victim showed that she had been suffocated to death. Dohad Superintendent of Police Rajdeep Singh Jhala said that a total of 10 teams were formed to investigate the

During the investigation, the police found that the parents had sent the girl to school with the school principal, Govind Nat, in his car. When she didn't return from school, the girl's parents asked Nat about her whereabouts, and



he said that he had dropped her at school. Following an investigation, the police took Govind Nat into custody and questioned him. During the

interrogation, Nat confessed to killing the girl as she resisted his attempts to rape her. Nat further said that when he tried to rape the girl, she started

screaming. He put his hands on her mouth tightly to stop her screaming.

However, the girl died, following which he hid her in the back of the car. After that, Govind Nat went to school as usual and taught the students. After the classes ended, he returned to the car, dumped her belongings near the school gate and left the girl's body behind the classroom. When the girl's parents along with locals reached the school in the evening of September

19, they found her belongings near the gate and they found her body in the

in Surat over 'sabotage' plot to get felicitated

3 rail staffers arrested

New Delhi. Three railway employees were arrested in Gujarat's Surat district on Monday for allegedly tampering with tracks and then alerting officials about a "sabotage" in a bid to take credit for averting a possible train accident, police said. Surat Rural Superintendent of Police (SP) Hotesh Joysar said the three employees -- Subhash Poddar (39), Manish Mistry (28) and Shubham Jaiswal (26) -are trackmen in the railways' maintenance department. He added that the accused indulged in such an act to get themselves felicitated. The Surat Police launched a probe after some unidentified people allegedly tampered with a railway track by removing fish plates and loosening several bolts in an attempt to derail trains on September 21.

The SP said Poddar and others, while on inspection between Kosamba and Kim stations, had alerted authorities at 5:30 am on September 21 about "miscreants" removing elastic clips and two fishplates from one set of tracks and placing them on another to derail a train. According to the SP, the accused, who were on night duty, had sent a video of the compromised truck to their seniors while alerting them. He also said the Railway officials had informed the police that a train had passed on the route just before the tampering was discovered. The time interval of the tampering being

discovered and the passing of the train was too less and it was not possible to remove the clips and plates in such a short time. We checked the mobile phones of the trio and found videos of tampered tracks shot at different intervals starting from 2:56 am to 4:57 am. Mistry had also deleted photos he had taken," SP Joysar said. The timings of the photos and videos shot were taken before the accused informed the officials about the incident around 5:30 am, the SP said, adding that the police became suspicious over the time interval. The three trackmen confessed to the crime after intense questioning and explained that they did such an act to ensure they would be felicitated and be deployed on night duty further, which would give them time to spend with the family during the day. "It was Poddar who came up with this idea because their night duty for the monsoon was about to

come to an end," SP Joysar said. He stressed that the accused, for each night duty session, would get a day off the following day and wanted the process to continue. Police had earlier said that unidentified people removed two fish plates that joined the ends of two rails on the railway track and placed them on the parallel track and also loosened some 40-50 bolts that hinged the railway track with the concrete sleepers.

Madhya Pradesh woman gang-raped after humiliating accused for splashing mud

New Delhi: A woman was gang-raped Kol, said he was travelling on a road humiliated by the woman in front of a after she humiliated a man who splashed mud on her while he was

driving his motorcycle in Madhya Pradesh's Rewa. Two people were arrested in connection with the incident. The incident occurred on September 22 (Sunday) when the victim, a college student, was on her way to get her mobile repaired at a shop. She was kidnapped and taken to a desolate

area where she was gang-raped.During

that had a lot of mud on his motorcycle. huge crowd, which embarrassed him. He said the mud splashed on the



questioning, the main accused, Kishan roadside. The accused said he was two accused were arrested.

Angered by the humiliation,

the accused decided to teach the victim a lesson.On September 22, Kishan Kol and his friend Santlal kidnapped the woman and took her behind the bushes, where they committed the crime. The woman informed her family about the incident, following which a complaint was filed. The victim's statement was recorded and her medical examination was conducted.Based on the

woman who was walking on the woman's complaint and statement, the

Badlapur sex abuse accused killed in police encounter: A timeline of events

New Delhi: Akshay Shinde, the prime accused who sexually abused two kindergarten girls at a school in Badlapur in Maharashtra's Thane district in August, died on Monday in a retaliatory firing after he snatched a policeman's gun and opened fire.Shinde (23), a sweeper employed at the school, was arrested on August 17 for sexually abusing the two girls, aged four and five, in a school toilet, four days ago. The incident had triggered widespread protests with parents and other locals blocking railway lines at Badlapur railway station before the police removed them forcibly.On Monday, Shinde was being taken from Taloja jail to Badlapur in connection with a case of unnatural sex filed by his former wife. According to the police, the accused snatched a weapon from an officer and opened fire while he was being transported from jail in a police vehicle. He was critically injured in the firing and

later died in hospital. The encounter triggered a war of words



between the Maharashtra government and the Opposition. Here is a timeline of when the incident unfolded to Shinde's death in the encounter:

August 13: Two kindergarten girls were sexually abused in a school toilet by Shinde in Badlapur. Shinde was employed on a contractual basis on August 1. August 16: The incident came to light when one of the victims narrated her ordeal to her

August 17: Shinde was arrested by the police after the incident came to light. August 20: 'Rail roko' protest at Badlapur protesters blocking railway tracks hindering train operations. Police later removed the protesters from the site.August 20: The ruling Mahayuti alliance suspended policeman who refused to initially file an FIR in the sexual abuse case. Later, three police officers were also suspended. August 20: The Maharashtra government forms a Special Investigation Team (SIT) to probe the Badlapur incident. August 20: People call for bandh. Parents and others protest and vandalise the school where the two girls were sexually abused. They later protested at the Badlapur railway station

August 21: The principal and two staffers working at Badlapur school were

accused be hanged in public.

for over 10 hours, demanding that the

suspended. August 22: The Bombay High Court took note of the case, questioning why no action was taken against the school. August 22: SIT begins a probe into the case.

railway station with hundreds of August 23: SIT adds Pocso sections against the school principal, secretary and chairman for not reporting the crime.September 3: The Bombay High Court urged the Maharashtra government to sensitise boys to be able to build a safe environment for girls to grow in society. It made the judgment while hearing a plea in the Badlapur sexual assault case.

September 16: SIT filed its first chargesheet in the case, based on the complaint of one of the girls. September 19: SIT filed its second chargesheet in the case, based on the second girl's complaint. September 23: Shinde allegedly snatched a policeman's gun and started firing. He is killed by a police officer while being taken to Thane by a Crime Branch SIT in a police vehicle to probe another sexual assault case filed by his former wife.

California passes law to ban smartphones in schools by 2026

Sacramento California Governor Gavin Newsom signed into law on Monday a bill that requires schools to limit or ban the use of smartphones, amid a growing consensus that excess usage can increase the risk of mental illness and impair learning.

Thirteen other states this year have banned or restricted cellphones in school or recommended local educators do so, after Florida led the way by banning phones in class in 2023, according to Education Week.California, with nearly 5.9 million public school students, has followed the lead of its own Los Angeles County, whose school board banned smartphones for its 429,000 students in June. That same month US Surgeon General Vivek Murthy called for a warning label, on social media platforms, akin to those on cigarette packages, likening the problem to a mental health emergency.

Murthy cited a study, in the medical journal JAMA showing adolescents who spend more than three hours a day on social media may be at heightened risk of mental illness, while referring to a Gallup poll, showing the average teen spends 4.8 hours per day on social media. California's bill, which passed 76-0 in the state assembly and 38-1 in the senate, requires school boards or other governing bodies to develop a policy to limit or prohibit student use of smartphones on campus by July 1, 2026, and update the policy every five years."We know that excessive smartphone use increases anxiety, depression, and other mental health issues but we have the power to intervene. This new law will help students focus on academics, social development, and the world in front of them, not their screens, when they're in school," Newsom said in a

Tsunami hits Japanese islands after 5.9magnitude earthquake, residents on alert

World A small tsunami hit Japan after an earthquake of magnitude 5.9 hit an unpopulated island in the Pacific Ocean on Tuesday. According to the Japan Meteorological Agency, a tsunami of 50 cm (1.6 feet) entered Hachijo island, one of the Izu islands, around 40 minutes after the earthquake.Smaller tsunamis have been detected on three other islands, Kozushima, Miyakejima and Izu Oshima as well, the weather body said. No casualties have been reported due to the tsunami or the earthquake

The weather body has also issued a warning for a tsunami of around 1 m (3.3 feet) high for Izu and Ogasawara islands. About 21,500 people live on the islands in the Izu group and about 2,500 on the Ogasawara Islands, news agency The Associated Press reported. Meanwhile, record rains hit central Japan's Noto region on Saturday, killing at least one person and ovr seven people were reported missing. Hourly rainfall hit record 121 mm (4.8 inches) on Saturday morning in Wajima, while neighbouring Suzu received 84.5 mm in an hour, also an all-time high.

A massive 7.6 magnitude earthquake hit Suzu, Wajima and surrounding areas in Japan in January this year, killing more than 300 people. Japan is situated on the Pacific Ring of Fire, a line of seismic faults in the Pacific Ocean, and is one of the world's most earthquake and tsunami-prone countries.

'Hezbollah Has Used You'...: Day After Deadly Strikes, Israeli PM Netanyahu Sends Out Message For Lebanese Citizens

Source Amid the ongoing deadly conflict between Israel and Hezbollah, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the Lebanese people, emphasizing that Israel's military actions are not aimed at them but specifically targeted at Hezbollah. Notably, his remarks come in the wake of Israeli strikes on Monday that resulted in the deaths of nearly 500 Lebanese citizens.In his video message shared online, Netanyahu said, "For a long time, Hezbollah has used you as human shields. They have stored rockets in your homes and missiles in your neighborhoods. These weapons are aimed directly at our cities and citizens, and to defend our people from Hezbollah's attacks, we must destroy these weapons."Warning the Lebanese people, Netanyahu further said, "Earlier today, the military started advising you to evacuate the danger zone. I strongly encourage you to take this warning seriously. Don't let Hezbollah jeopardize your safety or that of your loved ones. Don't allow Hezbollah to place Lebanon in harm's way."Deadly Israeli AttacksLebanon's Hezbollah-led Health Ministry reported 492 casualties as of Monday night, including 35 children and 58 women. According to the reports, at least 1,645 people were injured, and thousands of families had been forced to flee their homes. According to Lebanese officials, the recent wave of attacks marks the deadliest since the 2006 conflict between Israel and Hezbollah. The Israeli military urged civilians in southern and eastern Lebanon to evacuate as it intensifies its airstrikes on Hezbollah positions.

Donald Trump Says He Won't Seek Reelection if He Loses İn 2024 US Presidential Election

► The 78-year-old former president is pitched in a tight race with Democratic presidential candidate Vice President Kamala Harris. Trump would be 82 by the time of the next elections in 2028.

World Former US president Donald Trump has ruled out running for the White House in 2028 if he loses his presidential bid in November this year. "No, I don't. No, I don't. I think that that will be, that will be it. I don't see that at all. I think that hopefully we're gonna be successful," Trump told host Sharyl Attkisson in an interview over the weekend. Trump is running for presidential elections for the third consecutive term this time. He won the first time in 2016 and lost in his second attempt in 2020. The 78-year-old former president is pitched in a tight race with Democratic presidential candidate Vice President Kamala Harris. Trump would be 82 by the time of the next elections in 2028. The presidential elections in the US will take place on November 5. When asked what keeps him healthy, Trump said he plays golf and tries to eat properly. "Well, I used to play golf a little bit. That gave me, so I don't know, but it seems to be quite a dangerous sport in retrospect. I try and eat properly.
I try. I do the best," the
Republican presidential
candidate said. "I like perhaps
all the wrong food. But then I

say 'Does anybody know what the right food is?'" he asked. "I have people lecturing me for years, 'Oh don't eat this, don't eat that'. They're gone, they have passed away long ago," Trump said. During the interview, Trump stressed that he does not get credit for the fight against COVID-19. I never got great credit on the fighting of the

China virus, which is COVID. But we call it the China virus 'cause we like to be accurate.



But if you think of what I've done, I took, I took a disaster that came into our shores. That dust flew in from China and we started making things like the ventilators. We were supplying the whole world with ventilators," he said. "Within a period of seven months, we took auto factories and started making ventilators and auto factories. We did the gowns, the cost, you know, all of the

products, the masks, all, everything. And we also had to go, because our, you know, when I took over, the cupboards were bare. We had nothing," Trump said."We had, we were supposed to have, but we had nothing. And in all fairness to previous presidents, the reason is that nobody really thought a pandemic in this world, in this age, was possible. You know, you remember 1917, we had the great pandemic that people talk about. A hundred million people they say died," he said.

'And basically this would've happened here too. And it didn't happen here. I think I did a great job. I think I will not be given credit for it. But there are a lot of people that think I did a really fantastic job on that. Nobody knew what it was. Nobody knew where it came from. And remember, we had far fewer deaths than (incumbent President Joe) Biden. And Biden just got the tail end. So we did a good job,' Trump claimed.

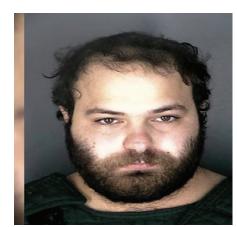
Gunman who killed 10 at Colorado supermarket in 2021 gets life imprisonment

Ahmad Al Aliwi Alissa, 25, had pleaded not guilty by reason of insanity. The jury instead found the Syria-born man guilty in Boulder District Court on 10 counts of firstdegree murder.

Denver, The man who killed 10 people in a mass shooting at a Colorado grocery store in 2021 was convicted on Monday of firstdegree murder and sentenced to life in prison without the possibility of parole.

Ahmad Al Aliwi Alissa, 25, had pleaded not guilty by reason of insanity. The jury instead found the Syria-born man guilty in Boulder District Court on 10 counts of first-degree murder. Jurors also found him guilty on dozens of counts of attempted murder and weapons offenses.

After relatives of the victims addressed the court, Judge Ingrid Bakke formally gave Alissa the mandatory sentence under Colorado law of life in prison without the possibility of parole.Colorado Governor Jared Polis said in a statement that "though I know this guilty verdict won't heal the those who were killed, I hope that it can



provide some peace."

It was never in dispute that Alissa carried out the rampage. The case focused on his mental state at the time of the shootings. Under Colorado law, a person must be found to be unable to distinguish between right and wrong for an insanity defense to prevail. Authorities said Alissa was armed with a legally purchased Ruger AR-556 pistol, which resembles an AR-15 semiautomatic rifle, when he entered the King Soopers grocery store in Boulder, about 30 miles (50 km) northwest of Denver, on March 22, 2021. Alissa shot dead two people in the parking lot before entering the store and killing eight others, including a police officer who responded to the shooting.

pain so many of us feel, or bring back He is methodical and he is brutal," District Attorney Michael Dougherty told jurors in

closing arguments on Friday. The psychologists and psychiatrists who testified during the trial that began last month agreed that Alissa was diagnosed as a schizophrenic who was profoundly mentally ill. But that diagnosis alone does not render a person legally insane.

This tragedy was born out of disease, not choice," defense attorney Kathryn Herold told the jury.Eyewitnesses described Aissa as focused as he opened fire, shooting dead at least two victims at point-blank range after wounding them in the opening salvo.

Sarah Chen, a pharmacist working that day, testified during the trial that she heard Alissa shriek with delight as he fired his weapon as she and other workers crouched behind a counter. Alissa did not testify in his own defense.

Erika Mahoney, whose father Kevin was killed in the shooting, told the court during victim impact statements on Monday that shortly after learning of her father's murder she envisioned standing in court and facing the gunman.

"I wish the young man behind the gun had received more love in his life, because then maybe none of this would have happened," Mahoney said.

She recounted other high-profile shootings that have plagued the United States in recent decades, and told the court ahead of Alissa's sentencing: "To me, justice is putting an end to mass shootings in

Pope asks for liberation of Myanmar's detained ex-leader Aung San Suu Kyi, offers Vatican as safe haven

Rome. Pope Francis has called for the liberation of Myanmar's detained former leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi and offered the Vatican as a safe haven, the pontiff said in a recent conversation with Jesuits in Asia.

'I asked for the Ms Aung San Suu Kyi's release and received her son in Rome. I offered the Vatican to receive her in our territory," he said in a private conversation during a recent 12-day tour across Southeast Asia. The 87-year old pontiff visited Myanmar in December 2017.Suu Kyi has been detained by the military since it overthrew her government in a 2021 coup. It is unclear where the hugely popular 78-year-old is being held or if she has been allowed any visitors. Italian daily Corriere della Sera published the comments on Tuesday in an article by Father Antonio Spadaro, a Rome-based Jesuit priest who attends the meetings and writes about them afterwards with the pope's permission."The future of the (Myanmar) must be peace based on respect for the dignity and rights of all, on respect for a democratic order that allows everyone to contribute to the common good," Pope Francis added.Suu Kyi, the British-educated daughter of Myanmar independence hero Aung San, has been jailed for a total of 27 years for crimes ranging from treason and bribery to violations of telecommunications and disaster management laws, which she denies. Her supporters say the cases were politically motivated to keep her out of the spotlight and stifle pro-democracy forces. The military maintains Suu Kyi was given due process.On Tuesday, a source familiar with Suu Kyi's previous legal cases, who declined to be identified due to the sensitivity of the issue, said her lawyers had no access to her to relay any

Russia says Ukraine's incursion into Kursk region killed 56 civilians

* Kyiv began the cross-border attack on August 6, more than two years after Moscow sent tens of thousands of troops into Ukraine, and Ukrainian forces remain in the Kursk region.

Moscow At least 56 civilians have been killed and 266 wounded during Ukraine's sevenweek-old incursion into Russia's western Kursk region, the Russian Foreign Ministry

said on Monday.Kyiv began the crossborder attack on August 6, more than two years after Moscow sent tens of thousands of troops into Ukraine, and Ukrainian forces remain in the Kursk region. The Russian Foreign Ministry had earlier put the death toll at 31 in the period to September 5. The new toll covered the period up to Sept. 20.It said 131,000 civilians had left the most dangerous areas of the region but accused Ukrainian forces of holding some civilians against their will, including 70-120 people in the town of Sudzha. Asked by Reuters about the statement, Ukrainian Foreign Ministry spokesman Heorhiy Tykhyi said Ukraine abides by international humanitarian law and does not target civilians, and that it was unable to verify the assertions."Given Russia's long history of false numbers and



propaganda, there is simply no way of verifying their claims. If Russia wants to show the real situation on the ground it can grant such access to the UN and ICRC," he said.Reuters was unable to immediately verify battlefield reports from either side. Both sides have denied targeting civilians and making false claims for propaganda

purposes during the 31-month-old conflict. The Kremlin has previously made clear it regards Ukraine's invitation to the United Nations and International Committee of the Red Cross to the Kursk region as "provocative", and that Moscow expects the UN and ICRC not to accept the invitation.

Kyiv has said its incursion, the biggest foreign attack on Russia since World War Two, is intended partly to prevent Russian forces in the area launching their own incursion across the border into Ukraine.Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said earlier this month that his forces controlled 100 settlements in Kursk region over an area of more than 1,300 sq km (500 sq miles). Russian sources disputed this figure and Russia says it has since taken back some villages in a counter-attack.

What to know about the growing conflict between Israel and Lebanon's Hezbollah

CAIRO. The past week has seen a rapid escalation in the nearly yearlong conflict between Israel and Lebanon's Hezbollah. First came two days of exploding pagers and walkie-talkies used by Hezbollah in deadly attacks pinned on Israel that also maimed civilians across Lebanon. Hezbollah's leader vowed to retaliate, and on Friday the militant group launched a wave of rockets into northern Israel. Later in the day, the commander of Hezbollah's most elite unit was killed in a strike in Beirut that killed dozens more people. The cross-border attacks ramped up early Sunday, with Here are some things to know about the Hezbollah, an Iranian-backed Shiite group situation: launching more than 100 rockets deeper into northern Israel, with some landing near the city of Haifa. Israel launched hundreds of strikes on Lebanon. Then, on Monday, Israel launched a series of strikes that killed more than 490 Lebanese, the deadliest attack since the 2006 Israel-Hezbollah war. Israel warned residents in southern and eastern Lebanon to leave their homes ahead of a spreading air campaign against Hezbollah.Many fear the escalating violence could lead to an all-out war between Israel and Hezbollah, which would further destabilise a region already shaken by the fighting in Gaza. Both sides have said they don't want that to happen,

even as they have defiantly warned of heavier attacks.Israel and Hezbollah have launched repeated strikes against each other since the Gaza war began, but both sides have pulled back when the spiral of reprisals appeared on the verge of getting out of control, under heavy pressure from the U.S. and its allies. But in recent weeks, Israeli leaders have warned of a possible bigger military operation to stop attacks from Lebanon to allow hundreds of thousands of Israelis displaced by the fighting to return to homes near the border.

that is Lebanon's most powerful armed force, More than 1,600 Lebanese were injured in Monday's deadly strikes and thousands more fled southern Lebanon. Israel said it was targeting Hezbollah weapons sites, and had hit some 1,600 targets. Lebanon's health minister said hospitals, medical centres and ambulances had been struck.

> The Israeli military warned residents to immediately leave areas where Hezbollah is storing weapons. The Lebanese media said the evacuation warning was repeated in text messages.Hezbollah said it had fired dozens of rockets toward Israel, including at military bases, and officials said a series of air-raid sirens were ringing out in northern Israel

Israeli airstrike brought down a high-rise building in Beirut's southern suburbs, killing Ibrahim Akil, the commander of Hezbollah's elite Radwan unit, and other top unit leaders. Israel said Akil led the group's campaign of rocket, drone and other fire into northern Israel. At least 45 people were killed in that

attack and more than 60 were wounded. That strike came after the shock of the electronic device bombings, in which thousands of pagers and walkie-talkies used by Hezbollah detonated on Tuesday and Wednesday. At least 37 people were killed, including two children, and around 3,000 were wounded. Israel has neither confirmed nor denied its involvement. Analysts say that attack had little effect on Hezbollah's manpower, but could disrupt its communications and force it to take tighter security measures.

What is the situation on the border?

The Israel-Lebanon border has seen almost daily exchanges since the Israel-Hamas war began on Oct. 7. Before Monday, the exchanges had killed around 600 people in Lebanon – mostly fighters but also about 100 civilians and about 50 soldiers and civilians in Israel. It has also forced hundreds of thousands of people to evacuate homes near the border in both Israel and Lebanon.

warning of rocket attacks.On Friday, an Hezbollah leader Hassan Nasrallah promised

to retaliate for the electronic device bombings. But Hezbollah also has proved wary of further stoking the crisis. The group faces a difficult balance of stretching the rules of engagement by hitting deeper into Israel in response to its brazen attacks, while at the same time trying to avoid the kind of large scale attacks on civilian areas that can trigger a full-scale war that it could be blamed for. Hezbollah says its attacks against Israel are in support of Hamas. Last week, Nasrallah said the barrages won't end and Israelis won't be able to return to homes in the north until Israel's campaign in Gaza

What is Israel planning?

Israeli officials say they haven't yet made an official decision to expand military operations against Hezbollah and haven't said publicly what those operations might be. Last week, though, the head of Israel's Northern Command was quoted in local media as advocating for a ground invasion of Lebanon. Meanwhile, as fighting in Gaza has slowed, Israel has increased its forces along the Lebanese border, including the arrival of a powerful army division believed to include thousands of troops. Israeli Defense Minister Yoav Gallant last week declared the start of a "new phase" of the war as Israel turns its focus toward Hezbollah..

England captain Heather Knight handed suspended fine over 2012 racist photo

New Delhi, England women's cricket captain Heather Knight has received a reprimand and a suspended fine of 1,000 pounds after admitting to a charge related to a 2012 social media post, according to England's Cricket Regulator on Monday.

The post in question featured Knight in blackface at a fancy dress party held at a cricket club in Kent. The image in question had recently resurfaced on social media and was considered offensive and a violation of the ECB's directive 3.3, which covers "acts or omissions prejudicial to the interests of cricket or likely to bring cricket or cricketers into disrepute."Despite the breach, the Cricket Discipline Commission (CDC) clarified that Knight's actions were without "racist or discriminatory intent.""The independent Cricket Discipline Commission (CDC) has issued its sanctions



decision in relation to Heather Knight after she was charged over a non-recent photograph which appeared on social media.""Ms Knight admitted a breach of ECB Directive 3.3 which stated at the time of the offence in 2012*: "No such person may conduct himself in a manner or do any act or omission which may be prejudicial to the interests of cricket or which may bring the game of cricket or any Cricketer or group of Cricketers into disrepute." read the statement from the CDC.

What did Knight say about fine?

At the time of the incident, Heather Knight was 21 years old and has since apologised, acknowledging her naivety. She emphasised that there was no malicious intent behind her actions and expressed regret for any offense caused."I'm truly sorry for the mistake I made in 2012. It was wrong, and I have long regretted it. Back then, I simply was not as educated as to the implications and consequences of my actions as I have become since. There was no ill-intent meant. Whilst I can't change the past.

Vishy's children are all grown up: Garry Kasparov praises India's Olympiad win

New Delhi. Chess legend Garry Kasparov heaped praise on the Indian contingent after their historic double gold at the 2024 Chess Olympiad. India made history in Budapest on Sunday, September 22, by winning gold in both the men's and women's events at the Chess Olympiad. Following the men's team's groundbreaking triumph, the women's team, consisting of Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Divya Deshmukh, Vantika Agrawal, Tania Sachdev, and Abhijit Kunte, secured gold, marking a historic double victory for India.In the final round, India ominated Azerbaijan with a 3.5-0.5 win. Harika, Divya, and Vantika secured victories in their respective matches, while Vaishali held a draw. Despite this emphatic result, India's gold in the women's open section was not guaranteed. Their title hopes hinged on

the USA holding Kazakhstan. India were crowned champions when the USA



managed to secure a 2-2 draw against Kazakhstan on Sunday. Had Kazakhstan won, the competition would have gone to tiebreaks. Earlier, key victories from D Gukesh and Arjun Erigaisi propelled India to their first-ever Chess Olympiad title on Sunday, September 22. Competing in Budapest, India triumphed over Slovenia in the final round, surpassing China to claim the title in the open section. Taking to X, Kasparov praised the Indian contingent for their win. The chess legend claimed that 'Vishy's children' had all grown up and the game is coming home."A very impressive double gold achievement by India. "Vishy's children" are all grown up and chess is coming home! Two American flags on the podiums as well, worthy of note. Add Uzbekistan and Kazakhstan, with no European flags," Kasparov. Viswanathan Anand was happy to see the Indian contingent's performance and also claimed that Gukesh is a contender to win the World Championship title against Ding Liren.

Thought Ding would sit out, wanted to give Pragg, Gukesh a rest and asked them to mute notifications: The inside story

→India captain Srinath explains behind-the-scenes ups and downs at the chess Olympiad

SHARJAH. South Africa denied Afghanistan a series sweep with a sevenwicket win in the third and final cricket ODI on Sunday.

Aiden Markram's unbeaten 69 led South Africa to 170-3 with 17 overs to spare in the one-day international after Afghanistan collapsed for the first time in the series and was bowled out for 169 in 34

Afghanistan won the series 2-1.

An inexperienced South Africa was dismissed for 106 and 134 in the first two games, but Markram paced the chase well on yet another slow wicket at Sharjah Cricket Stadium with a gritty 67-ball innings."Feeling very happy with the series win," Afghanistan captain Hashmatullah Shahidi said. "I would be more happy if we would have won this match." He called the three runouts of his team's batters "a big reason why we didn't

was missing its ace legspinner Rashid Khan because of a hamstring injury.

Earlier, Rahmanullah Gurbaz, who made a century in the last game, held the innings together by contributing 89 runs in 94 balls after Afghanistan chose to bat first. But none of the other top eight Afghan batters could score more than 10 with three of them run out.No. 9 batter AM Ghazanfar made a whirlwind 31 not out off 15 but South Africa always looked in control through the

disciplined bowling of Lungi Ngidi, Nqabayomzi Peter and Andile Phehlukwayo, who all picked up two wickets each. South Africa finally got used to the conditions in the United Arab Emirates as their pace bowlers Ngidi and Phehlukwayo were well supported by some superb fielding. Ngidi tested the batters upfront through his cutters and slow balls and pinned debutant opener Abdul Malik leg before wicket inside the power play. Ngidi then had Rahmat Shah



run out when Gurbaz's drive clipped his fingers in the follow through and hit the stumps at the non-striker's end. Shahidi was run out while going for a second run and Ikram Alikhil met a similar fate when he went too far down the wicket before Gurbaz sent him back as Afghanistan slipped to 113-5 in the 22nd over. South Africa should have dismissed Mohammad Nabi on 5 but captain Temba Bavuma didn't go for the television referral against Bjorn Fortuin's arm ball before the spinner

had Nabi caught behind in his next over.Gurbaz tried to accelerate in search of his second successive century before he holed out to Reeza Hendricks at extra cover but Ghazanfar's late flurry ensured Afghanistan crossed the 160-run mark.Bavuma (22) and Tony de Zorzi (26) provided South Africa with a solid start of 40 and controlled the power play before Bavuma was undone by offspinner Ghazanfar and clean

De Zorzi was twice dropped off Nabi's successive deliveries

before Nabi had him trapped lbw and Hendricks' run of poor form continued when he mistimed a pull shot and was caught after scoring 18.

Markram and Tristan Stubbs controlled the chase with their match-winning 90-run stand with Stubbs 26 not out.

We were quite clinical with the bat," Bavuma said. "In terms of series, not what we planned for, (but) the guys will take a lot of experience and learning from it."

R Ashwin responds to

Bumrah's 'fittest' remark after

after social media storm

New Delhi. Off-spinner Ravichandran Ashwin

downplayed the discussion surrounding

Jasprit Bumrah's 'fittest cricketer' comment,

which sparked debate among fans on social

media. Ashwin mentioned that it's

unreasonable to ask a cricketer a question and then expect his response to please everyone.

The veteran also called Bumrah the

'Kohinoor' of Indian cricket, praising him as

one of the standout fast bowlers of the modern

era.Jasprit Bumrah's reply to 'India's fittest

cricketer' question at a promotional event led

to debates on social media. Some fans

disagreed with Bumrah and even suggested

he should have taken Virat Kohli's name. A

section of them even targeted Bumrah for not

Ashwin, however, highlighted the workload

concerns for Jasprit Bumrah and said it has

naming Kohli in his reply.

Chess Olympiad: Susan Polgar meets 'amazing Chess Mom' after India's double

At the 2024 Chess Olympiad in Hungary, chess legend Susan Polgar had the opportunity to meet and greet Nagalakshmi, the mother of Indian chess stars Praggnanandhaa and Vaishali. Polgar expressed her excitement at meeting the 'amazing chess mom' and posed for a memorable photograph with the family.

Budapest. Legendary chess player Susan Polgar met and greeted Nagalakshmi, the mother of Indian chess prodigies Praggnanandhaa and Vaishali, during the Chess Olympiad in Hungary. The former world champion expressed her excitement at meeting Nagalakshmi, referring to her as an 'Amazing Chess Mom' and commending her for the unwavering support she has provided in shaping the careers of her two children.

Polgar's meeting with Nagalakshmi took place on the sidelines of the recently-concluded Chess Olympiad. India made history by

winning gold medals in both the Open and Women's sections in Budapest, the home of the renowned Polgar sisters. Praggnanandhaa played a crucial role in the men's team's commanding performance, while Vaishali was instrumental in helping the women's team secure its first-ever gold medal at the Olympiad.

"I had to meet this amazing Chess Mom, who devoted her life to raising two super Chess Stars!" Polgar wrote, sharing photos with Nagalakshmi, Praggnanandhaa, and Vaishali. The brother-sister duo from Chennai has been making waves in the chess world, becoming the first siblings to both achieve Grandmaster titles and qualify for the Candidates Tournament.

Nagalakshmi has been ensuring that her children maintain a healthy lifestyle, providing them with homemade food and

encouraging them to stay focused on their game. Both Praggnanandhaa and Vaishali have spoken at length about their mother's support in helping them adjust to tough conditions, especially in overseas tournaments. The chess stars' father, Rameshbabu, works as a branch manager at a bank in Chennai. Also Read: India's dominant Chess Olympiad win reminds Viswanathan Anand of

Soviet teams In Hungary, Indian chess stars grabbed the spotlight over the weekend after their unprecedented success in the Olympiad. Susan Polgar had shared a video of the chess players celebrating like Indian men's cricketer team captain, Rohit Sharma, during the trophy presentation ceremony. As expected, the clip went viral.

The men's team, led by Grandmasters D Gukesh, Arjun Erigaisi, and R Praggnanandhaa, secured the top spot with a dominant 3.5-0.5 victory over Slovenia in the final round, finishing with 21 points. The women's team, featuring D Harika, R Vaishali, Divya Deshmukh, and Vantika Agrawal, also won 3.5-0.5 against Azerbaijan, claiming the gold with 19

Manchester City's Rodri set to miss rest of season with ACL tear: Reports

New Delhi. Manchester City midfielder Rodri is expected to miss the remainder of the season after tests on Monday indicated he

suffered an anterior cruciate ligament (ACL) tear in his right knee during Sunday's 2-2 draw with Arsenal, according to a report from ESPN. Further tests are planned, but the signs point toward a serious injury, with Rodri likely to undergo surgery in Barcelona. This means that Rodri could be out of action for up to 9

City salvaged a last-minute equalizer through John Stones to secure the draw at the Etihad Stadium, keeping them at the top of the Premier League table with 13 points from five games. However, the biggest low point for

them was when Rodri had to be taken off the field after sustaining an injury to his right leg during a corner sequence for the defending Premier League champions. The Spanish midfielder would immediately go down early in the first half, clutching his leg and in visible distress.Rodri would then have to be

taken away from the field with the help of the City medical staff and was replaced by Mateo Kovacic. Rodri, who was named the



player of the tournament at Euro 2024 after helping Spain to victory, is amongst the frontrunners for the Ballon d'Or. The 28year-old had recently voiced concerns about player workloads, hinting that players were close" to striking. Rodri played 63 matches for club and country last season, with his campaign extending until the Euro 2024

final on July 14."I think we are close to that; it is easy to understand. I think it's something general. I think if you ask any player, he will

say the same -- it is not the opinion of Rodri or whatever. I think it's the general opinion of the players. And if it keeps this way, there will be a moment where we have no other option, I really think, but let's see. I don't know what's going to happen, but it's something that worries us because we are the guys that suffer." Rodri's injury a serious setback for

Rodri's injury is a major setback for City as they pursue their fifth consecutive Premier League title. Guardiola's side are yet to face the

likes of Liverpool, Tottenham Hotspur and Manchester United this season and the midfielder will certainly leave a big void for the defending champions. City will be facing Watford in the 3rd round of the Carabao Cup on September 24, Tuesday, before taking on Newcastle United in the Premier League on Saturday, September 28.

been remarkable to see the fast bowler recover from his long-standing back injury concerns and return to his best, consistently clocking speeds of 145 kph and above. Ashwin likened a fast bowler to a 'tipper lorry', highlighting the wear and tear they go through, especially when bowling in hot and humid conditions. Why do you want to make this thing big? Jasprit Burmrah is a fast bowler who clocks 145 kph in the scorching heat, slogs so hard. He is the crowned jewel of Indian cricket. Bumrah is India's Kohinoor diamond. Let Jasprit Bumrah say whatever he wants to, just accept it," Ashwin said in his Hindi YouTube show. "Tell me one thing: Has any fast bowler after Kapil Dev become as big? Bumrah comes and wins you matches. Also, you asked Jasprit Bumrah the question, and then you also only wanted to answer it. You are saying, 'I am not satisfied with your answer'. How is this fair?"

'A FAST BOWLER IS A TIPPER LORRY'

Ashwin acknowledged that Virat Kohli is among the fittest cricketers going around and highlighted that it's not even fair to compare a fast bowler and a batter.

If I were Vinesh Phogat, I would apologise for Olympic disqualification: Yogeshwar

New Delhi Olympic medalist Yogeshwar Dutt disqualification was the right call. They criticised Vinesh Phogat, stating that the wrestler did not take responsibility after the Paris Olympics, instead blaming others for her disqualification. Yogeshwar, who won a bronze medal at the London Olympics, said that if he had been disqualified, he would have apologised to the entire nation. He expressed disappointment with how Vinesh handled the highly-publicised ordeal.

Speaking at the Panchayat AajTak Haryana 2024 event, Yogeshwar said he was surprised when Vinesh started spreading conspiracy theories about her Olympic disqualification. He even claimed that Vinesh went as far as blaming Prime Minister Narendra Modi for the incident."She was disqualified from the Olympic Games, she should have apologised own. made mistakes. But instead, she termed it a VINESH

disqualify athletes even if the weight is more by a gram," Yogeshwar said. Yogeshwar's comments came just days after Vinesh made serious allegations against the Indian Olympic Association (IOA) and its president, PT Usha. Phogat criticised the IOA for not providing adequate legal support during her appeal to the Court of Arbitration for Sport (CAS) for a joint silver medal. Despite her efforts, the CAS ruled against her. Vinesh argued that the Government of India and the IOA should have taken a more proactive role in filing and supporting her case, instead of joining the process only after she had initiated it on her

in front of the entire nation, saying that she FALSE PERCEPTION WAS CREATED:

conspiracy, even blaming the Prime Minister Yogeshwar accused Vinesh Phogat of even "If we speak just about the Olympics, despite of the country. Everyone knows that the manipulating wrestlers during the much-



publicised wrestlers' protest against former Wrestlng Federation of India officials, including Brij Bhushan Sharan Singh.

"She created a wrong atmosphere in the country. Even during the protests, people were asked to gather in the wrong way.

costing India a medal, a false perception was

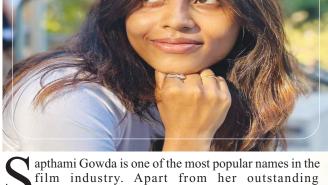
created that something wrong happened to her. If I was in Vinesh's place, I would've apologised to the country," he added. Vinesh was disqualified for being 100 grams overweight during the weighin on the day of her final. Vinesh made a sensational run to the final of the women's 50 kg category at the Paris Olympics and was on the cusp of glory before the disqualification.Senior lawyer Harish Salve, who represented Phogat in the CAS hearing, countered some of her allegations by stating that there was a lack of coordination between the different legal teams involved, and that Phogat

herself chose not to pursue further legal action after the CAS verdict. Following her disqualification and the rejection of her appeal, Phogat announced her retirement from wrestling and has since entered politics, joining the Indian National Congress.



Cowda

Blends Comfort And Style In Chic White Tee Look



apthami Gowda is one of the most popular names in the film industry. Apart from her outstanding performances, Sapthami is also known for her active social media presence. The actress always keeps her fans updated on both her personal and professional lives. In her recent visit to the Yosemite National Park, Sapthami Gowda grabbed her fans' attention, not just with the stunning backdrop but also with her effortlessly stylish look. The young actress, known for her roles in Kannada cinema, took to Instagram to share moments from her trip, showcasing her fashion sense that perfectly blends comfort with style.

Sapthami Gowda pulled off a simple yet elegant white t-shirt, a go-to choice for a day out in nature. Her minimalistic approach to dressing was enhanced by her choice of accessories like a subtle yet stylish necklace and a classic ring that added just the right amount of sparkle without dominating her natural beauty. Her hair was left loose in natural waves, framing her face beautifully as she basked in the golden-hour sunlight, which highlighted her features. The actress opted for a light makeup look, flexing her clear skin and bright smile. Her photos went viral in no time, while fans showered compliments in the comment section.

Sapthami Gowda works primarily in Kannada cinema. She made her acting debut in 2020 with the film Popcorn Monkey Tiger, directed by Duniya Suri. The film was produced by KM Sudhir and serves as a sequel to the 2015 film Kendasampige. The film features Dhananjaya, Amrutha Iyengar, Nivedhitha, Sapthami Gowda, Sparsha Rekha and Prashanth Siddi in pivotal roles. The actress got the limelight for her role of Leela in Kantara, directed by Rishab Shetty, in 2022. She is a recipient of a Filmfare Award South and two SIIMA Awards



Pragya Jaiswal's

Glammed Up Black Bodysuit Look Will Drive Your Monday Blues Away

Pragya Jaiswal is a true blue fashionista and you can't deny it. When it comes to making a bold fashion statement, the diva doesn't hold back and effortlessly showcases her captivating style with sheer elegance. Once again, the actress set the internet ablaze with her stunning look in an all-black bold outfit that she opted for a recent photoshoot. She dolled up in a stunning one-piece black bodysuit. Needless to say, she looked extremely hot and sizzling. Her outfit featured full sleeves and a deep V-neckline. For the glam quotient, Pragya opted for a dewy base with defined brows, smokey eyeshadow, mascara-coated lashes and a dark brown lip shade that complemented her overall look. She styled her hair in a nearly drenched open look

as though she had just walked out of the pool minutes ago.In the photo, Pragya Jaiswal could be seen striking a sexy pose on top of what seems like the handle of a sofa set. "So far, so good," she wrote in the caption.

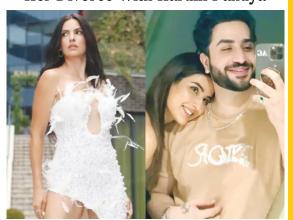
As soon as the actress dropped the picture, the comment section was flooded with reactions from her fans and admirers. An Instagram user wrote, "Looking radiant." Another one commented, "Koi itna khoobsurat kaise ho sakta hai (how can someone be so beautiful)." One of them wrote, "You are pure beauty."

Pragya Jaiswal was recently seen in the comedy-drama film Khel Khel Mein. Directed by Mudassar Aziz, the film also

featured Akshay Kumar, Taapsee Pannu, Vaani Kapoor, Fardeen Khan, Ammy Virk and Aditya Seal in the lead roles. Khel Khel Mein, despite getting positive reviews from critics and fans, didn't perform well at the box office. The film is an official Hindi remake of the 2016 Italian flick Perfetti Sconosciuti (Perfect Strangers). Pragya is a popular name in the South film industry and has appeared in several films like Virattu, Kanche, Akhanda and many more. She made her Bollywood debut with the film Titoo MBA in 2014. She will reportedly be next seen in south star Nandamuri Balakrishna's upcoming film tentatively titled NBK109. It also stars Bobby Deol, Jagapathi Babu and Niddhi Aggarwal in the leads.



Natasa Stankovic 'Likes' Aly Goni's Cozy Photo With Jasmin Bhasin After Her Divorce With Hardik Pandya



Aly Goni and Jasmin Bhasin are one of the most adorable celebrity couples and there is no doubt about it. The two often share their love-filled pictures online and leave their fans in complete awe. On Monday too, Aly took to his Instagram handle and dropped a romantic picture with his ladylove Jasmin. In the photo, they were all smiles as Jasmin rested her head on Aly's shoulder as he took a mirror selfie. However, what grabbed everyone's attention was something else. Soon after the photo was shared online, netizens noticed that among others, Natasa Stankovic also liked it. Before Jasmin, Aly was in a romantic relationship with Natasa Stankovic. They even appeared together on the 9th season of Nach Baliye but broke up soon after the show ended.

nterestingly, this comes days after Aly Goni dropped a big hint about his breakup with Natasa. He appeared on Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa's podcast when he talked about his past relationship. Even though the actor did not name Natasa, he mentioned that they broke up because she wanted to not live with his family."Jo mera isse pahle bhi relation tha, voh bahut hi serious tha. Uska reason hi yahi tha ke usne mujhe bola ke 'yaar jab hum shaadi kareinge future mein hum alag raheinge'. Voh cheez mujhe nahi jami (My previous relationship was very serious. The reason we broke up was that she told me that we would live separately. I did not agree to it)," Aly said. Goni, who is currently seen in Laughter Chefs, further mentioned that he is a family man and does not want to live separately. "Main apne family ko saath leke chalunge jahab bhi jaaunga. Main family ko alag nahi kar sakte. Main nahi chod sakta, chahe duniya ki koi bhi taakat aa jaaye (I will take my family along wherever I go. I cannot separate from my family. I can't leave them, come what may)," he added.Meanwhile, Natasa Stankovic recently parted ways from her cricketer husband Hardik Pandya. The two, who tied the knot in May 2020 and renewed their wedding vows according to the Hindu and Christian rituals in February 2023, confirmed their separation in July 2024.

Justin Bieber And Hailey Bieber Are Even 'More In Love' Since The Arrival Of Baby Boy: Report



Canadian singer Justin Bieber and his wife Hailey Bieber recently became parents. They welcomed a baby boy, Jack Blues Bieber, sometime in August. Since the birth of their first child, the couple has been more focused on raising their baby and embracing their parental duties. Recently, a source disclosed that the couple seemed "more in love" just after a month of their baby boy's arrival. People quoted a source who shared that the Bieber couple had a quiet celebration for their sixth anniversary. Justin and Hailey got married in a courthouse wedding in September 2018 in New York City. The insider said, "They had a quiet wedding anniversary celebration. They seem even more in love since the baby arrived." The source added that the Rhode founder has been "feeling great" after becoming a mother, whereas the Stay singer has been encouraging his wife to catch up with her friends. And keeping up with her husband's request, Hailey was recently spotted with her good friend Kylie Jenner in LA.

The source continued, "(Justin has) been in a happy bubble since baby Jack was born. He wants to focus on being a great dad and husband." For those who don't know, Justin shared a post on his Instagram on August 23 announcing the arrival of his baby boy. He posted a picture featuring a tiny foot and a well-manicured hand of Hailey. Captioning the post, the singer wrote, "WELCOME HOME JACK BLUES BIEBER." The couple has named their first kid after Justin's father Jeremy Bieber, whose middle name is Jack.

Just days after Justin and Hailey's son's birth, a source disclosed to People that their baby is everything that they ever wished for. "The pregnancy was something that they very much wished and prayed for."

The day they found out that Hailey was pregnant was the best ever for Justin. He was over the moon with excitement. It was a big celebration for them," read the report. Ever since the couple got married, there were frequent rumours about their pregnancy. The Canadian singer surprised his millions of fans when he dropped an ethereal video from his vow renewal ceremony on May 10.

